



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 12 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 21, 1942 शक संवत्) [संख्या 36**

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	909—918	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	647—664	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण		975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	151—168	975	भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	485—510	975
			स्टोस—पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

**भाग 1**

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

**भाषा विभाग**

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

10 अगस्त, 2020 ई0

सं0 143/इक्कीस-1-2020-5 (3)/94-टी0सी0-II-उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, लखनऊ के उपाध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किये जाने विषयक इस अनुभाग के पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या सी0एम0-3/इक्कीस-1-2019-5 (3)/94-टी0सी0-II, दिनांक 26 जुलाई, 2019 के क्रम में अधोवर्णित महानुभावों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदनाम के अनुसार उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से पुनः एक वर्ष के लिये एतद्द्वारा नामित किया जाता है—

क्रमांक	पदधारियों का नाम	पदनाम
1	श्री सरदार इकबाल सिंह, लखनऊ	उपाध्यक्ष
2	श्री जगनैन सिंह, 'नीटू', गोरखपुर	सदस्य
3	श्री गुरविन्दर सिंह छाबड़ा (सरदार), कानपुर	सदस्य
4	श्री गुरुभाग सिंह, पीलीभीत	सदस्य
5	श्री जसविन्दर सिंह, जौनपुर	सदस्य
6	श्री जगदीश साधना, गाजियाबाद	सदस्य

2—उक्त कार्यकाल बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

3—उपर्युक्त नामित महानुभावों के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के अनुसार यथा प्राविधानित सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

आज्ञा से,  
जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव।

**गृह विभाग**

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

शुद्धि-पत्र

13 अगस्त, 2020 ई0

सं0 17/2020/309/छ:पु0से0-1-2020-02 डी0पी0सी0 (एसएल-2)/2019—अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13, रु0 1,18,500-2,14,100) में प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश/प्रोन्नति संख्या 8/2020/232/छ:पु0से0-1-2020-02 डी0पी0सी0 (एसएल-2)/2019, दिनांक 11 फरवरी, 2020 निर्गत किया गया है।

2—वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 11/2017/वे0आ0-2-563/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 27 जुलाई, 2017 द्वारा ग्रेड पे रु0 8,700 के लिये मैट्रिक्स पे-लेवल-13 को संशोधित करते हुये रु0 1,18,500-2,14,100 के स्थान पर रु0 1,23,100-2,15,900 किया गया है।

3—अतः वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश के अनुक्रम में कार्यालय आदेश/प्रोन्नति संख्या 08/2020/232/छ:पु0से0-1-2020-02 डी0पी0सी0 (एसएल-2)/2019, दिनांक 11 फरवरी, 2020 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उक्त आदेश में अंकित वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13, रु0 1,18,500-2,14,100 के स्थान पर वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13, रु0 1,23,100-2,15,900 पढ़ा जाय।

4—उपर्युक्त संशोधन के अतिरिक्त कार्यालय आदेश/प्रोन्नति संख्या 08/2020/232/छ:पु0से0-1-2020-02 डी0पी0सी0 (एसएल-2)/2019, दिनांक 11 फरवरी, 2020 में अंकित अन्य विवरण/शर्तें यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,  
अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव।

## वित्त विभाग

[लेखा परीक्षा]

अनुभाग-1

अतिरिक्त प्रभार

17 अगस्त, 2020 ई0

सं0 14/2020/आडिट-1-373/दस-2020-320 (4)/2018—श्री राज्यपाल, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	चित्रकूटधाम मण्डल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जनपद चित्रकूट।
2	श्रीमती कुसुम यादव, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	जनपद अयोध्या	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जनपद अम्बेडकरनगर।

2—जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा तथा उपरोक्त अधिकारियों को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिये अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 15/2020/आडिट-1-407/दस-2020-320 (4)/2018—श्री राज्यपाल, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में उल्लिखित जनपद में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पूर्णकालिक रूप से तैनात करते हुये कालम-4 में अंकित संस्था का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से सौंपे जाने के आदेश प्रदान करते हैं—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम/पदनाम	जनपद	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	श्री राजेन्द्र यादव, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी चीनी मिल, सेमीखेड़ा, बरेली	बरेली	सहकारी चीनी मिल, सेमीखेड़ा, बरेली।

2—उपरोक्त अधिकारी को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिये अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,  
समीर,  
विशेष सचिव।

## राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

तैनाती/स्थानान्तरण

11 अगस्त, 2020 ई०

सं० राज्य कर-1-771/11-2020-107/19—वाणिज्य कर विभाग के श्री अवधेश कुमार सिंह-1, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (अपील) सहारनपुर को स्थानान्तरित करते हुये एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर (वि०अनु०शा०), मुरादाबाद के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,  
राजेश कुमार त्यागी,  
विशेष सचिव।

शुद्धि-पत्र

10 अगस्त, 2020 ई०

सं० राज्य कर-1-526-1/11-2020-106/19—शासन के विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेश संख्या राज्य कर-1-501/11-2020-106/19 टी०सी०, दिनांक 29 जून, 2020 एवं आदेश संख्या राज्य कर-1-526/11-2020-106/19 टी०सी०, दिनांक 01 जुलाई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के कतिपय एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 (कुल 08) के पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेशों में यह शर्त टंकित होने से छूट गयी है कि “उपर्युक्त पदोन्नति आदेश विभिन्न मा० न्यायालय/मा० अधिकरण के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होंगे।”

अतः उक्त विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेश संख्या राज्य कर-1-501/11-2020-106/19 टी०सी०, दिनांक 29 जून, 2020 एवं आदेश संख्या राज्य कर-1-526/11-2020-106/19 टी०सी०, दिनांक 01 जुलाई, 2020 को इस शर्त के साथ कि “उपर्युक्त पदोन्नति आदेश विभिन्न मा० न्यायालय/मा० अधिकरण के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होंगे” पढ़ा जाय।

2—विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेश संख्या राज्य कर-1-501/11-2020-106/19 टी०सी०, दिनांक 29 जून, 2020 एवं आदेश संख्या राज्य कर-1-526/11-2020-106/19 टी०सी०, दिनांक 01 जुलाई, 2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,  
अरविन्द कुमार,  
संयुक्त सचिव।

## तैनाती

29 जुलाई, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-669/11-2020-12/2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित नवनियुक्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर को कालम-2 में अंकित सम्बद्धता के स्थान से कालम-3 में अंकित रिक्त पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	तैनाती
1	2	3
1	श्री यतीन्द्र कुमार, सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, इटावा	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, हापुड़
2	सुरेश कुमार पाल, सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, अयोध्या	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, चन्दौसी
3	श्री अरविन्द कुमार निषाद, सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, गाजियाबाद जोन प्रथम	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-10, मुरादाबाद
4	श्री मोहम्मद दानिश, सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाराणसी जोन प्रथम	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, बलरामपुर
5	सुश्री पारूल राजवंशी, सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, लखनऊ जोन प्रथम	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-17, लखनऊ
6	श्री सुरेन्द्र कुमार, सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, गोरखपुर	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, नजीबाबाद
7	श्री अशोक प्रिय गौतम, सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, गाजियाबाद जोन प्रथम	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, मथुरा
8	श्री राहुल कुमार, सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाराणसी जोन द्वितीय	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, बिजनौर
9	श्री अजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सम्बद्ध कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, फतेहपुर

सं0 राज्य कर-1-669-1/11-2020-12/2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित नवपदोन्नत असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर (पूर्व पदनाम सहायक आयुक्त, मनोरंजन कर) को कालम-3 में अंकित रिक्त पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	नवीन तैनाती
1	2	3
1	श्री देवेन्द्र पाल सिंह	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-4, गाजीपुर।
2	श्री रोशन लाल	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-5, गोरखपुर।
3	श्री सुभाष	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
4	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-5, आगरा।

आज्ञा से,  
राजेश कुमार त्यागी,  
विशेष सचिव।

## कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति-पत्र

18 अगस्त, 2020 ई0

सं0 602/22-1-2020-306/98टीसी-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार अधीक्षक कारागार के पद नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अमित चौधरी पुत्र श्री उदयवीर सिंह चौधरी, ग्राम-पटलोनी, पोस्ट-पटलोनी, तहसील-महावन, जिला-मथुरा, उ0प्र0, पिनकोड-281301 (अनुक्रमांक-299296) को उत्तर प्रदेश कारागार सेवा में अधीक्षक कारागार समूह 'ख' (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400) के पद पर श्री राज्यपाल सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

2—श्री अमित चौधरी की नियुक्ति इस शर्त के अधीन की जाती है कि उनकी सेवायें, उ0प्र0, जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 1982 एवं यथासंशोधित सेवा नियमावलियों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3—श्री अमित चौधरी को महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के कार्यालय से सम्बद्ध करते हुये तैनात किया जाता है तथा उन्हें एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह कारागार सेवा में अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों, तो इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तैनाती स्थान पर उपस्थित हों।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्री अमित चौधरी निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मानते हुये कि वह नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, नियमानुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4—श्री अमित चौधरी उ0प्र0 जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 1982, यथासंशोधित सपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक परीक्षा नियमावली, 2013 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अधीक्षक, कारागार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

5—श्री अमित चौधरी की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा तैयार की गयी मेरिट सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

6—यदि कोई याचिका विचाराधीन है, तो प्रश्नगत नियुक्ति उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,  
अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव।

## संस्कृति विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त, 2020 ई0

सं0 823/चार/2020—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियमेंट मानूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट, 1904 (अधिनियम संख्या 7, 1904) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करते हैं :

## अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/ स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा संख्या	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	तहसील- मार्टिंगंज, ग्राम-देहदुआर	प्राचीन टीला (कोट)	460 एवं 461	हेक्टेयर 1.535 1.619 <u>3.154</u>	पूर्व-आबादी पश्चिम- आबादी एवं देहदुआर मार्ग उत्तर- आबादी एवं गाटा संख्या 547 दक्षिण- आबादी एवं गाटा संख्या 554, 557 एवं 558/616

## सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, आजमगढ़ को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,  
जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification  
**No. 823/Four-2020**, dated August 18, 2020 for general information :

**No. 823/Four-2020**

August 18, 2020

In exercise of the powers under sub-section (1) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956. (U.P. Act no. VII of 1957), the Governor is pleased to propose to declare the ancient monuments described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act no. VII of 1904 :

## SCHEDULE

Sl. no.	State	District	Tahsil and Village	Name of the monument sites	Revenue plots to be taken under protection	Area in Acres/ Hectare	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Pradesh.	Azamgarh	Tahsil- Martinganj, Vill.- Dehduwar.	Old Tila (Kott)	460 and 461 <b>Total ..</b>	<b>Hectare</b> 1.535 1.619 <u><b>3.154</b></u>	East-Aabadi. West-Aabadi and Dehduwar Road. North-Aabadi and Gata no. 547. South-Aabadi and Gata nos. 554, 557 and 558/616.

**INTIMATION**

Objection if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/ Director U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh, Lucknow or District Azamgarh within one month from the date of the publication of this notification.

By order,  
JITENDRA KUMAR,  
Principal Secretary.

**लोक निर्माण विभाग**

अनुभाग-3

पदोन्नति

10 अगस्त, 2020 ई0

सं0 27/2020/1116/23-3-2020-02 (डब्ल्यू) ईएस/2020-उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री वहीद बख्श (ज्येष्ठता क्रमांक-1856) को उनके कनिष्ठ श्री राजीव गोविल (ज्येष्ठता क्रमांक-1858) की अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 12 जुलाई, 2019 से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (पे-मैट्रिक्स लेवल-13) में नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-श्री वहीद बख्श, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,  
प्रभुनाथ,  
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

नियुक्ति

14 अगस्त, 2020 ई0

सं0 1047/23-4-2020-45 ए0ई0/2017 टी0सी0-श्री श्याम बिहारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी के विरुद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1960/23-13-13-27(3) ईएम/13, दिनांक 12 जुलाई, 2013 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2222/23-13-17-27 (3) ईएम/13, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 द्वारा श्री श्याम बिहारी को परिनिन्दित करते हुये उनकी 01 वार्षिक वेतन वृद्धि 01 वर्ष तक के लिये अस्थायी प्रभाव से रोकने जाने के दण्ड के साथ समाप्त की गयी। श्री श्याम बिहारी के विरुद्ध तत्समय दण्डादेश प्रभावी होने के कारण उन्हें चयन वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया तथा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 682/23-4-18-45 ईई/2017, दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा श्री श्याम बिहारी (ज्येष्ठता क्रमांक-4118) से कनिष्ठ श्री उमेश चन्द्र सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-4119) को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।

2-उक्त दण्डादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 के विरुद्ध श्री श्याम बिहारी द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका संख्या 602/2018 योजित की गयी, जिसमें पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 10 मई, 2019 द्वारा दण्डादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को निरस्त कर दिया गया। मा0 अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 10 मई, 2019 के अनुपालन में शासन के आदेश संख्या 1317/23-13-19-8(सी0पी0)/18, दिनांक 02 अगस्त, 2019 द्वारा सन्दर्भित दण्डादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को निरस्त करते हुये यह निर्देश प्रसारित किये गये कि उक्त दण्डादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 के आधार पर रोके गये समस्त परिणामिक सेवालाभ याची श्री श्याम बिहारी को अनुमन्य करा दिये जाय।

3—निर्देश याचिका संख्या 602/2018 में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 10 मई, 2019 के अनुपालन हेतु श्री श्याम बिहारी द्वारा मा0 अधिकरण के समक्ष अवमानना याचिका संख्या 320/2019, श्याम बिहारी बनाम श्री नितिन रमेश गोकर्ण बनाम व अन्य योजित की गयी है।

4—अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में श्री श्याम बिहारी द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में एक अन्य निर्देश याचिका संख्या 1254/18, श्याम बिहारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी जिसमें दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :

Claim petition succeeds. Opposite parties are directed to consider the petitioners case for promotion in accordance with law on the post to Assistant Engineer with effect from the date juniors were promoted. Compliance of this judgment shall be made within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this judgment.

5—मा0 अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 के अनुपालन हेतु याची श्री श्याम बिहारी, अवर अभियन्ता (सिविल) द्वारा अवमानना याचिका संख्या 65/2020 श्याम बिहारी बनाम श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व अन्य योजित की गयी है।

6—श्री श्याम बिहारी की कनिष्ठ की भांति दिनांक 23 मार्च, 2018 से पदोन्नति किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या 2043/23-4-19-45 एई/2017 टी0सी0, दिनांक 06 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के विचारार्थ संदर्भित किया गया। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में शासन के पत्र संख्या 367/23-4-20-45 एई/17 टी0सी0, दिनांक 28 फरवरी, 2020 द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 से 30 जून, 2019 तक की अवधि के लिये सहायक अभियन्ता का एक अधिसंख्य पद सृजित किया गया।

7—चयन वर्ष 2019-20 में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर चयन के सम्बन्ध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में सम्पन्न चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 414/23-4-20-06 एन0जी0/2019, दिनांक 13 मार्च, 2020 द्वारा श्री श्याम बिहारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।

8—शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 06 नवम्बर, 2019 के क्रम में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 653/06/पी/एस-6/2019-20, दिनांक 31 जुलाई, 2020 द्वारा मा0 आयोग की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी।

9—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, श्री श्याम बिहारी, तत्कालीन अवर अभियन्ता (सिविल) (ज्येष्ठता क्रमांक-4118) को उनसे कनिष्ठ श्री उमेश चन्द्र सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-4119) की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर की गयी पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 23 मार्च, 2018 से वेतन बैण्ड-2, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित पे बैण्ड-3 के लेवल-10) में नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

10—श्री श्याम बिहारी का वेतन निर्धारण कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के प्रस्तर-1 (8) व 1 (9) में निहित प्राविधानानुसार निर्धारित किया जायेगा।

11—श्री श्याम बिहारी उक्त पदोन्नति सिविल अपील संख्या 3695/2007, अतिबल सिंह बनाम श्री प्रमोद शंकर उपाध्याय व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2019 के अनुक्रम में मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गठित की जाने वाली खण्डपीठ में पारित होने वाले निर्णय तथा रिट याचिका संख्या 16986/2019, मार्कण्डेय तिवारी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,  
डा0 चन्द्र भूषण,  
विशेष सचिव।

## आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनुभाग-8

अधिसूचना

15 जुलाई, 2020 ई०

सं० 718/आठ-8-2020-38एलयूसी/2019-चूँकि, राज्य सरकार कानपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर महायोजना-2021 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" तथा "अमर उजाला" के संस्करण में दिनांक 21 मार्च, 2020 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित), 1974 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 30, सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, कानपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत, कानपुर महायोजना, 2021 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

### अनुसूची

क्र०सं०	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	कानपुर महायोजना-2021 के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
1	मकसूदाबाद	735-ख	2.930	वनीकरण	स्टेडियम/क्रीड़ा स्थल

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित भूमि के बदले निम्नलिखित भूमि को "वनीकरण" भू-उपयोग में परिवर्तन किया जाता है, जो निम्नवत् है—

क्र०सं०	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	कानपुर महायोजना-2021 के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
1	सुरार	607	1.199	लघु/हल्के उद्योग	वनीकरण
2		561	0.020	लघु/हल्के उद्योग	वनीकरण
3		561-ख	1.711	लघु/हल्के उद्योग	वनीकरण
		योग . .	2.930		

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 12 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 21, 1942 शक संवत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

#### NOTIFICATION

[ESTABLISHMENT SECTION]

June 26, 2020

**No. 13**—From the date of taking over charge, following 01 Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar in the pay scale Level-11, with the condition that his promotion shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	6059	Sri Sanjai Kumar Srivastava

**No. 14**—From the date of taking over charge, following 01 Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Section Officer in the pay scale Level-10, with the condition that her promotion shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7348	Smt. Prachi Pandey, Lko.

(In view of prevailing transfer policy, Smt. Prachi Pandey will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad as Section Officer).

July 26, 2020

**No. 15**—From the date of taking over charge, Sri Brijesh Kumar, Registrar-cum-Bench Secretary (Senior Grade) (Emp. No. 3266), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Registrar-cum-Principal/Head Bench Secretary, High Court, Allahabad in the pay scale

of P.B. 4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,900 (Level-13-A Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Naveen Prakash Srivastava.

**No. 16**—From the date of taking over charge, Sri Rajesh Kumar Goel, Joint Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-IV, (Emp. No. 3175), High Court, Allahabad is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Bench Secretary, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,900 (Level-13-A Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Shyam Kumar Chaurasia.

**No. 17**—From the date of taking over charge, Sri Sirajuddin, Joint Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-IV, (Emp. No. 2622), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Registrar-cum-Bench Secretary, (Senior Grade), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in the pay scale, of P.B. 4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,900 (Level-13-A Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Brijesh Kumar.

**No. 18**—From the date of taking over charge, Sri Kamlakar Dwivedi, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-III, (Emp. No. 3330), High Court, Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-IV, High Court, Allahabad, in the pay scale of P.B. 4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,700 (Level-13 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Nand Lal Yadav.

**No. 19**—From the date of taking over charge, Sri Lal Chand, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-III, (Emp. No. 3375), High Court, Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-IV, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,700 (Level-13 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Rajesh Kumar Goel.

**No. 20**—From the date of taking over charge, Sri Ram Singh, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-III, (Emp. No. 2633), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in the pay scale of P.B. 4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,700 (Level-13 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Sirajuddin.

**No. 21**—From the date of taking over charge, Sri Rajesh Kumar Mishra, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-II, (Emp. No. 4057), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Rakesh Chandra Pandey.

**No. 22**—From the date of taking over charge, Sri Sushil Kumar, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-II, (Emp. No. 4042), High Court, Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-III, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to Promotion of Sri Kamlakar Dwivedi.

**No. 23**—From the date of taking over charge, Sri Raghvendra Singh, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-II, (Emp. No. 6042), High Court, Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-III, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Lal Chand.

**No. 24**—From the date of taking over charge, Sri Anil Kumar Srivastava-IV, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-II, (Emp. No. 3345), High Court, Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-III, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-

39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Ram Singh.

**No. 25**—From the date of taking over charge, Sri Vineet Srivastava, Bench Secretary, Grade-I, (Emp. No. 7144), High Court, Allahabad is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-II, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Rajesh Kumar Mishra.

**No. 26**—From the date of taking over charge, Sri Sayed Arif Hussain, Bench Secretary, Grade-I, (Emp. No. 2973), High Court, Allahabad is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-II, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Sushil Kumar.

**No. 27**—From the date of taking over charge, Sri Alok Kumar, Bench Secretary, Grade-I, (Emp. No. 7101), High Court, Allahabad is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-II, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Raghvendra Singh.

**No. 28**—From the date of taking over charge, Mrs. Nanda Priya, Bench Secretary, Grade-I, (Emp. No. 2978), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Bench Secretary, Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Anil Kumar Srivastava-IV.

(All the promotions, notified above, shall be subject to result or Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Padam Prakash Srivastava, Emp. no. 2760, D.R.-cum-B.S. Grade-III and Sri Pritam Kumar Singh, Emp. no. 2955, A.R.-cum-B.S. Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow who have been permitted to draw salary from High Court, Allahabad shall draw salary from High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow. Sri Rajesh Kumar Mishra, Emp. no. 4057 and Mrs. Nanda Priya, Emp. no. 2978, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow shall draw salary from High Court, Allahabad as D.R.-cum-B.S. Grade-III and A.R.-cum-B.S. Grade-II respectively).

**No. 29**—From the date of taking over charge, Sri Shahid Husain, Joint Registrar-cum-Private Secretary, Grade-IV, (Emp. No. 1028), High Court, Allahabad, is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Private Secretary, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,900 (Level-13-A Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Chakkar Prasad Pandey.

**No. 30**—From the date of taking over charge, Sri Sanjeev Kumar Sachdeva, Deputy Registrar-cum-Private Secretary, Grade-III, (Emp. No. 1464), High Court, Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Private Secretary, Grade-IV, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,700 (Level-13 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Anil Kumar Jaiswal.

**No. 31**—From the date of taking over charge, Sri Atul Kumar Srivastava, Deputy Registrar-cum-Private Secretary, Grade-III, (Emp. No. 1462), High Court, Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Private Secretary, Grade-IV, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,700 (Level-13 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to Promotion of Sri Shahid Husain.

**No. 32**—From the date of taking over charge, Sri Afzal Husain Abbasi, Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, (Emp. No. 1529), High Court, Allahabad is hereby promoted as Deputy

Registrar-cum-Private Secretary, Grade-III, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Nawab Ahmad Khan.

**No. 33**—From the date of taking over charge, Sri Baratam Vidya Sagar, Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, (Emp. No. 1524), High Court, Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary, Grade-III, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Sanjeev Kumar Sachdeva.

**No. 34**—From the date of taking over charge, Sri Nishith Dey, Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, (Emp. No. 1526), High Court, Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary, Grade-III, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Atul Kumar Srivastava.

**No. 35**—From the date of taking over charge, Sri Rakesh Mehta, Private Secretary, Grade-I, (Emp. No. 2926), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Afzal Hussain Abbasi.

**No. 36**—From the date of taking over charge, Sri Pravin Verma, Private Secretary, Grade-I, (Emp. No. 3511), High Court, Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, High Court, Allahabad, in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Baratam Vidya Sagar.

**No. 37**—From the date of taking over charge, Sri Ishan Jaiswal, Additional Private Secretary, (Emp. No. 3638), High Court, Allahabad, is hereby promoted as Private Secretary, Grade-I, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 5,400 (Level-10 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Rakesh Mehta.

**No. 38**—From the date of taking over charge, Sri Rajesh Kumar Maurya, Additional Private Secretary, (Emp. No. 3647), High Court, Allahabad, is hereby promoted as Private Secretary, Grade-I, High Court, Allahabad, in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 5,400 (Level-10 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Pravin Verma.

(All the promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Private of this Court).

**No. 39**—Sri Arvind Kumar Shashank (Emp. no. 7285), Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is promoted as Section Officer, notionally *w.e.f.* 05-12-2019 A.N. [the date his junior Sri Vijendra Singh (Emp. no. 7286) has been promoted to the post of Section Officer] along with all consequential benefits and his name is placed above the name of Sri Vijendra Singh (Emp. no. 7286) in gradation list of Section Officer.

**No. 40**—Sri Neeraj Srivastava (Emp. no. 3334), Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad is promoted to the post of Section Officer from the date of consideration of his promotion, *i.e.* 23-07-2020, subject to his joining/taking charge on the post of Section Officer. His promotion shall be subject to final decision of Criminal Case no. 539 of 1991 under section 498-A/304-B I.P.C. and 3/4 of Dowry Prohibition Act, 1991 pending against him.

August 05, 2020

**No. 41**—From the date of taking over charge, Sri Vinod Kumar Jaiswar, (Emp. No. 1466), Deputy Registrar-cum-Private Secretary, Grade-III, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Private Secretary, Grade-IV, in the pay scale of P.B. 4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,700

(Level-13 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Sabih Uddin.

**No. 42**—From the date of taking over charge, Sri Sunil Kumar Singh, (Emp. No. 1525), Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary, Grade-III, in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Vijay Kumar Srivastava.

**No. 43**—From the date of taking over charge, Sri T. Lakshman Kumar, (Emp. No. 2924), Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary, Grade-III, in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to Promotion of Sri Vinod Kumar Jaiswar.

**No. 44**—From the date of taking over charge, Sri Suresh Chandra, (Emp. No. 2923), Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary, Grade-III, in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the vacancy caused due to voluntary retirement of Sri Rakesh Kumar.

**No. 45**—From the date of taking over charge, Sri Puneet Srivastava, (Emp. No. 1596), Private Secretary, Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to Promotion of Sri Sunil Kumar Singh.

**No. 46**—From the date of taking over charge, Sri Nitin Kumar, (Emp. No. 1586), Private Secretary, Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to Promotion of Sri T. Lakshman Kumar.

**No. 47**—From the date of taking over charge, Sri Kushal Agarwal, (Emp. No. 3513), Private Secretary, Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to Promotion of Sri Suresh Chandra.

**No. 48**—From the date of taking over charge, Ms. Mini Kanaujiya, (Emp. No. 3648), Additional Private Secretary, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Private Secretary, Grade-I, in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 5,400 (Level-10 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy to be occurred due to Promotion of Sri Puneet Srivastava.

**No. 49**—From the date of taking over charge, Sri Munna Lal, (Emp. No. 6918), Additional Private Secretary, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Private Secretary, Grade-I, in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 5,400 (Level-10 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy to be occurred due to Promotion of Sri Nitin Kumar.

**No. 50**—From the date of taking over charge, Sri Mohd. Mustaqeem Khan, (Emp. No. 3548), Additional Private Secretary, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Private Secretary, Grade-I, in the pay scale of P.B. 3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 5,400 (Level-10 Revised as per 7<sup>th</sup> Pay Commission) in the consequential vacancy to be occurred due to Promotion of Sri Kushal Agarwal.

(All the promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

By order of  
Hon'ble The Chief Justice  
(Sd.) ILLEGIBLE,  
Registrar General.

## बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञा

04 अगस्त, 2020 ई०

सं० 737/डी०एल०आर०सी०/2020-शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1012) की धारा 59 की उपधारा 4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम हसनपुर, परगना जेवर, तहसील खुरजा, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, खुरजा के द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 875/र०का०-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 29 जुलाई, 2020 के आधार पर शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.266 हे०, 33/11 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु अंकन रु० 01.00 प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य के हिसाब से कुल रु० 1.00 पर 30 वर्ष के लिये पुनर्ग्रहण के माध्यम से पट्टे पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल द्वितीय सेक्टर 16, नोएडा के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है तथा भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त रु० 13.14 मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया अंकन रु० 1971 कुल रु० 1972.00 प्राप्त किया जायेगा, जो विद्युत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा—

### अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
हे०							
बुलन्दशहर	खुरजा	जेवर	हसनपुर	85/2	0.266	5-3 ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	उ०प्र० शासन के विद्युत विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुये 33/11 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु।

रविन्द्र कुमार,  
जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

## मेरठ के जिलाधिकारी की आज्ञा

10 अगस्त, 2020 ई०

सं० 754/सात-डी०एल०आर०सी०/स्वामित्व योजना/2020-उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-14, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 434/एक-14/2020, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के द्वारा जनपद मेरठ के 672 ग्राम, ग्राम आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, गजट में अधिसूचना के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे गये हैं।

अतः मैं, अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी मेरठ, राजस्व परिषद के पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2020 के क्रम में उक्त अधिसूचना में प्रकाशित ग्रामों में से निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों में अधिसूचना के दिनांक से अभिलेख एवं सर्वेक्षण प्रक्रिया संपादित किये जाने हेतु आदेश देता हूँ—

### अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	परगना	विकास खण्ड	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	पबला
2					खरदौनी शेखूपुर
3					मसूरी
4		मवाना	हस्तिनापुर	मवाना	भगवानपुर
5					बना
6					नंगली ईशा
7					दूधली बांगर
8		सरधना	दौराला	दौराला	जमालपुर जलालपुर
9					मैल
10					अन्दावली

अनिल ढींगरा,  
जिलाधिकारी, मेरठ।

### भदोही के जिलाधिकारी की आज्ञायें

13 अगस्त, 2020 ई0

सं0 2020/डी0एल0आर0सी0/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

### अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हे0								
1	भदोही	औराई	भदोही	पुरे गुलाम	49-मि0	0.025	नवीन परती	बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उ0प्र0 शासन (आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु)।

सं0 2021/डी0एल0आर0सी0/2020-शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

#### अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हे0								
1	भदोही	औराई	भदोही	देवकली	200.00	0.024	बंजर	सिंचाई विभाग उ0प्र0 शासन (ट्यूबेल भवन देवकली हेतु)

सं0 2022/डी0एल0आर0सी0/2020-शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

#### अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हे0								
1	भदोही	औराई	भदोही	दत्तीपुर	270	0.153	ऊसर	शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन (कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, दत्तीपुर हेतु)

सं0 2023/डी0एल0आर0सी0/2020-शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश

दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

### अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हे०								
1	भदोही	औराई	भदोही	लीलाधरपुर	479-मि०	0.051	पुरानी परती	बेसिक शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन (प्राथमिक विद्यालय, लीलाधर पुर हेतु)।

सं० 2024/डी०एल०आर०सी०/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

### अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हे०								
1	भदोही	औराई	भदोही	उचेठा	195/650 208-च	0.013 0.013	नवीन परती पुरानी परती	बाल विकास एवं पुष्ठाहार विभाग उ०प्र० शासन (आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु)।

सं० 2025/डी०एल०आर०सी०/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश

दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

### अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हे०								
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	कसिदहं	1298-मि० 1297	0.063 0.003	पुरानी परती नवीन परती	बेसिक शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन (प्राथमिक विद्यालय, कसिदहं अनु०जाति बस्ती हेतु)।

राजेन्द्र प्रसाद,  
जिलाधिकारी, भदोही।

### मेरठ के जिलाधिकारी की आज्ञा

17 अगस्त, 2020 ई०

सं० 768/सात-डी०एल०आर०सी०/2019—शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित शक्तियों को उपयोग करते हुये, मैं अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी मेरठ, ग्राम अमीनगर उर्फ भूडबराल, तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 196 रकबा 0.0470 हे०, जो राजस्व अभिलेखों में खाद के गड्ढे के रूप में अंकित है तथा खसरा संख्या 640 रकबा 0.0470 हे०, जो राजस्व अभिलेखों में बंजर के रूप में अंकित है, का परस्पर विनिमय एवं श्रेणी परिवर्तन करते हुये खसरा संख्या 196 रकबा 0.0470 हे० को बंजर एवं भूमि खसरा संख्या 640 रकबा 0.0470 हे० को खाद के गड्ढे के रूप में परिवर्तित करता हूँ।

श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त खसरा संख्या 196 रकबा 0.0470 हे० बंजर भूमि स्थित ग्राम अमीनगर उर्फ भूडबराल, तहसील व जिला मेरठ को पुनः अपने अधिकार में लेता हूँ तथा यह भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुये दिल्ली गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल परियोजना हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम) को निम्न शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है—

### शर्तें

1—पुनर्गृहीत की जा रही भूमि का उपयोग, निर्धारित उपयोग से इतर नहीं किया जायेगा। यदि भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन हेतु किया जायेगा तो शर्तों के उल्लंघन की दशा में भूमि का पुनर्गृहण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

2—पुनर्गृहीत की जा रही भूमि का श्रेणी परिवर्तन अपवादात्मक परिस्थितियों में किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4(3) के अनुसार श्रेणी परिवर्तन शुल्क कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि अंकन रु० 2,23,250.00 लेखाशीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्ति-08 मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" में जमा कराये जाने के उपरान्त ही अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही की जायेगी।

3-शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) के अनुसार भूमि राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों को ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया देय होगा। पुनर्गृहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना, राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" में जमा कराया जायेगा। तदनुसार भूमि का मूल्य अंकन रु0 35,72,000 तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया अंकन रु0 176.25 निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने के उपरान्त कब्जा हस्तान्तरित किया जायेगा।

अनिल ढींगरा,  
जिलाधिकारी, मेरठ।

## जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

18 अगस्त, 2020 ई0

सं0 243/D.L.R.C/2020-21-शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0 प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 प्रदत्त प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम दौलारजपुरा, परगना सिकन्द्राबाद, तहसील व जनपद गौतमबुद्धनगर के प्रबंधन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में ली जाती है-

### अनुसूची

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हे0								
1	गौतमबुद्ध नगर	सदर	सिकन्द्राबाद	दौलारजपुरा	552	0.8430	श्रेणी-6(4) कृषि अयोग्य भूमि	उत्तर प्रदेश के सेवारत विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुये राजकीय महिला महाविद्यालय के निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित।

ह0 (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

## कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

07 अगस्त, 2020 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2017 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2019-20/2073/वाणिज्य कर-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री स्मृति गुप्ता पुत्री श्री विनोद कुमार गुप्ता, ग्राम व पोस्ट-दरियापुर नेवादा, मेहनाजपुर, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0-276203 (अनुक्रमांक-406560) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800+ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—सुश्री स्मृति गुप्ता नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगी। यह अवधि यथानियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—सुश्री स्मृति गुप्ता का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—सुश्री स्मृति गुप्ता की सेवायें समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4—सुश्री स्मृति गुप्ता को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5—सुश्री स्मृति गुप्ता को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अयोध्या जोन, अयोध्या के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री स्मृति गुप्ता को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

20 अगस्त, 2020 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2017 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/2207/वाणिज्य कर-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री राहुल त्रिपाठी पुत्र श्री हनुमान प्रसाद त्रिपाठी, म0नं0 7/9/30, गांधीनगर, नाका मुजफ्फरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या, उ0प्र0-224001 (अनुक्रमांक-185325) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800+ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—श्री राहुल त्रिपाठी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथानियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री राहुल त्रिपाठी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री राहुल त्रिपाठी की सेवायें समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4—श्री राहुल त्रिपाठी को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5—श्री राहुल त्रिपाठी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन प्रथम, गाजियाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री राहुल त्रिपाठी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अमृता सोनी,  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

### कार्यालय, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज

05 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 306-ख(निदे0)/20—मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 विभाग के अधिकारी जो अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त उसी माह के अन्तिम दिनांक (कालम नं0-7 में अंकित है) के अपरान्ह से वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2, से 4 के मूलनियम 56 (क) के अन्तर्गत यदि वे उसके पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं कर दिये जाते हैं तो सेवानिवृत्त हो जायेंगे :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पदनाम	वेतनमान	सेवानिवृत्त दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	स्व0 बोधई लाल	30-04-1961	कल्याण अधिकारी	56,100-1,77,500	30-04-2021

28 अगस्त, 2020 ई0

सं0 290-ख(निदे0)/20—श्री सोहन लाल पुत्र श्री दुखीराम, वित्त एवं लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ जिनकी जन्म तिथि 06 अक्टूबर, 1960 है, अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शासकीय सेवा से दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को सेवानिवृत्त होंगे। अतएव, श्री सोहन लाल को एतद्वारा निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 के अपरान्ह में अपने पद का प्रभार छोड़कर शासकीय सेवा से अवश्य सेवानिवृत्त हो जायें।

अतुल कुमार श्रीवास्तव,  
निदेशक,  
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,  
उ0प्र0, प्रयागराज।

## कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

23 जून, 2020 ई०

सं० 2491/जी०-153/61-2006—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

### ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बरेली	फरीदपुर	1	करतोली
		2	रसुइया
		3	भीकमपुर इ० शिवपुरी
		4	खनीनवादा
		5	समदा ई नगरिया

सं० 2492/जी०-151/65-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के ग्राम जमुवा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं० 2493/जी०-610/2006-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नानपारा, जनपद बहराइच के ग्राम सरैया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं० 2494/जी०-309/57—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील जलेसर, जनपद एटा के ग्राम रसीदपुर मितरौल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं० 2495/जी०-212/60-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांगरमऊ, जनपद उन्नाव के ग्राम दसगवां में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं० 2496/जी०-212/60-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-

टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सफीपुर, जनपद उन्नाव के ग्राम मखदूमनगर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

03 जुलाई, 2020 ई0

सं0 2576/जी0-226/62-08—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील विधूना, जनपद औरैया के ग्राम चन्दौली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2578/जी0-152-B/2018—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/ 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर के ग्राम राजापुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 4172/जी0-610/2012, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 2579/जी0-215/62—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/ 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम नवादा दरोबस्त में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के

अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 2418/जी0-610/2016-17, दिनांक 01 मई, 2018 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 2580/जी0-153/61-15—रिट याचिका संख्या बी0/2839/2019 नरेश पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के अनुक्रम में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या 4292/वि0प्र0/सा0, दिनांक 19 जून, 2020 द्वारा जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, बरेली की संस्तुति के आधार पर ग्राम ठकनी रजपुरी, तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रख्यापित करने के निर्देश के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 निस्तारित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/ 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली के ग्राम ठकनी रजपुरी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 1342/जी0-610/2012, दिनांक 24 मार्च, 2014 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 2581/जी0-357/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील एटा, जनपद एटा के ग्राम जीसुखपुर उर्फ नगला बरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2582/जी0-201/91(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, जनपद मीरजापुर के ग्राम चक भैसोड़ तप्पा उपरौध जो कि विज्ञप्ति दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 में ग्राम भैसोड़ चक के रूप में विज्ञापित किया गया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं० 2583/जी०-201/91-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, जनपद मीरजापुर के ग्राम डोहर तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

07 जुलाई, 2020 ई०

सं० 2672/जी०-175/59-98-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम झूरीकुइयाँ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं० 2659/जी०-225/62-रिट याचिका संख्या 429/बी०/2020 महेश सिंह व दो अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व दो अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा

पारित आदेश दिनांक 03 फरवरी, 2020 के अनुक्रम में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या 4327/वि०प्र०/सा०, दिनांक 29 जून, 2020 द्वारा ग्राम बरौलिया, तहसील खागा, जनपद फतेहपुर को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रख्यापित करने के निर्देश के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 25 फरवरी, 2020 निस्तारित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई०ए०-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील खागा, जनपद फतेहपुर के ग्राम बरौलिया में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 1426/जी०-610/2012, दिनांक 25 मार्च, 2014 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

16 जुलाई, 2020 ई०

सं० 2822/जी०-161/59-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरैया, जनपद बस्ती के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

#### ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बस्ती	हरैया	1	खजुरी तप्पा दुबौलिया
		2	पकौलिया तप्पा बेलवा
		3	हरदी खास तप्पा हरदी

20 जुलाई, 2020 ई०

सं० 2830/जी०-610/77-19-रिट याचिका संख्या 3068/बी०/2019 सहदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश

राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुक्रम में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या 4255/वि0प्र0/सा0, दिनांक 02 जून, 2020 द्वारा जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, एटा की संस्तुति के आधार पर ग्राम टिकाथर (टिकासर), तहसील अलीगंज, जनपद एटा को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रख्यापित करने के निर्देश के साथ याची का प्रार्थना-पत्र/प्रत्यावेदन दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 एवं सम विषयक अन्य प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अलीगंज, जनपद एटा के ग्राम टिकाथर (टिकासर) में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 1042/जी0-610/2012, दिनांक 21 फरवरी, 2014 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

21 जुलाई, 2020 ई0

सं0 2834/जी0-163/69—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद वाराणसी के ग्राम सरसौल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2835/जी0-159/65-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं,

बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद के ग्राम गतौरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2836/जी0-201/91(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, जनपद मीरजापुर के ग्राम नदौली तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2837/जी0-174/66-06(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के ग्राम मकरन्दपुर ता0 पिपरिया दुलई में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2838/जी0-354ए/60-15(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी

गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद के ग्राम मुजफ्फरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2880/जी0-181/66(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

#### ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
गोरखपुर	खजनी	1	नेउसा उर्फ नेवासमाफी तप्पा खजुरी
		2	सिवापार उर्फ सियरही तप्पा खजुरी

28 जुलाई, 2020 ई0

सं0 2934/जी0-164 धारा-6(1)/20-21—रिट याचिका संख्या 3043/बी0/2019 हफीजउल्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के अनुक्रम में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या 4360/वि0प्र0/सा0, दिनांक 13 जुलाई,

2020 द्वारा ग्राम बिलासपुर, परगना व तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रख्यापित करने के निर्देश के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 तथा प्रार्थना-पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 निस्तारित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी के ग्राम बिलासपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 3886/जी0-164/59-06, दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 2935/जी0-163/59—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सदर, जनपद हरदोई के ग्राम बेहटा गोकुल में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 1879/जी0-163/59, दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

बी0 राम शास्त्री,  
चकबन्दी संचालक,  
उत्तर प्रदेश।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 12 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 21, 1942 शक संवत्)

### भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,  
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

### खण्ड-घ-जिला पंचायत

19 अगस्त 2020 ई०

सं० स्था०नि०सहा०/इक्कीस-1(2015-16)563-उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961, जो उ०प्र० पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम सन् 1994 द्वारा संशोधित है की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, सुलतानपुर द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवनों, संस्थागत एवं शैक्षणिक तथा अन्य निर्माण गतिविधियों आदि के नक्शों, तलपट योजना एवं निर्माण को नियंत्रित व विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनायी गयी है। मेरे द्वारा उक्त उपविधि की पुष्टि कर दी गयी है एवं उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत सुलतानपुर द्वारा जनपद सुलतानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निम्नलिखित उपविधियां बनायी गयी हैं जिन्हें इस आशय से प्रकाशित किया जा रहा है कि यदि जनपद सुलतानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को इन उपविधियों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह इस प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर अपना लिखित आपत्ति या सुझाव जिला पंचायत, सुलतानपुर कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

### मानक उपविधि (MODEL BYE-LAWS)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) 1994 की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 95 एवं 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत सुलतानपुर ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र या उत्तर आवास विकास परिषद के अधीन क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों निर्माण एवं भू-खण्डों के विकास आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियाँ बनायी हैं—

### भाग-1

### प्रस्तावना एवं परिभाषायें

1-अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित)से है।

2—इन उपविधियों के क्रियान्वयन के लिये “ग्राम्य क्षेत्र” का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहित किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3—विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4—मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद् के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन, योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5—निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6—भवन की ऊँचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊँचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊँचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊँचाई में मस्ती, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊँचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7—छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुये भाग से है जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8—ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित हैं।

9—निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10—तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहाँ पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11—फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12—भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13—ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14—लेआउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भूखण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाले प्लान से है।

15—प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है —

(अ) अभियन्ता—अभियन्ता, जिला पंचायत सुलतानपुर से है।

(ब) अवर अभियन्ता— इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

(स) अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग का तात्पर्य जिस लोक निर्माण विभाग के सर्किल में जिला पंचायत स्थित है के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता से है।

(द) अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् का तात्पर्य जिला पंचायत के मुख्यालय में स्थित उत्तर प्रदेश आवास एवं परिषद् के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता से है।

16-कार्य अधिकारी/कर अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी/कर अधिकारी जिला पंचायत सुलतानपुर से है।

17-अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18-स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19-रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भूगर्भ जल के स्तर को ऊँचा उठाने से है।

20-सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथास्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउण्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21-अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सुलतानपुर से है।

22-जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1) में संगठित जिला पंचायत सुलतानपुर से है।

23-अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत सुलतानपुर से है।

24-बहु मंजिली भवन (Multy Storey)-भूतल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई का भवन बहुमंजिल कहलायेगा।

25-मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26-भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नेस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भूभाग को ढँकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27-आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्रावधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल हैं।

28-व्यावसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप, होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल, व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुषांगिक हो और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29-संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसों पैदा होती हों या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

30-भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31-पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहाँ पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

32—इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

## भाग—2

### उपविधि का नाम

ये उपविधियाँ जिला पंचायत सुलतानपुर के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र, जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाइटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का लेआउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियाँ कहलायेंगी।

## भाग—3

### नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियाँ

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा—

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी—

(अ) ये उपविधियाँ कच्चे मकानों एवं गाँव के मूल निवासी के शुद्धतया निजीआवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी, परन्तु सुरक्षित डिजाइन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(व) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड़ढा भरना।

## भाग—4

### प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

1—उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भूखण्ड के लेआउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

2—स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा —

(अ) लेआउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा।

(ब) की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा।

(स) बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा।

(द) स्थल के चारों तरफ की सीमाएँ, उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण।

(य) भूमि मालिक का नाम एवं पूर्ण पता।

(र) समीपवर्ती विद्यमान मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग/मार्गों की दूरी।

(ल) स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

3—प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा, जिसके साथ निम्न विवरण/सूचनायें दी जायेंगी:—

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा पूर्ण विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहितहस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर पंजीकृत स्ट्रक्चर डिजाइनर का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(द) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैण्डस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास, जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भूखंड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(श) नक्शे पर भूखंड का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

4-बहु मंजिली भवन (multy storey), भूतल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 12मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शों पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी :-

(अ) अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था, आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट, अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location),

(ब) निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की विशिष्टियाँ आदि।

#### भाग-5

#### नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन विस्तार की किसी भूखंड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी, यदि

(अ) प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों।

(स) प्रस्तावित निर्माण लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) हो अथवा आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

#### भाग-6

#### तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1-नक्शा/प्लान में निम्न अनुदेशों का पालन किया जायेगा-

(क) एक आवास गृह में 4.50 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लॉट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code), 2005 के प्रावधान के अनुसार गुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर, इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जाएगी। भूखंड के डेड इन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

2-निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भूखंड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उप केन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.40 मीटर एवं क्षेत्रफल 9.50वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (TOILET) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊंचे भवन में 1.50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

4-(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल, भूखंड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग परस्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रण्ट सेट बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाइनर की होगी।

5-स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal)की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6-बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रान्सफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

## भाग-7

### भूकम्परोधी सुरक्षात्मक व्यवस्थायें

1-District Disaster Management Authority गाजियाबाद के द्वारा जारी पुस्तक जो कि भारत सरकार UNDP के सहयोग से तैयार की गयी है, के पृष्ठ-39 पर दी गयी सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश को मोटे तौर पर भूकम्प के सम्बन्ध में 3 Risk Zone में बाटा गया है। जिनका वर्गीकरण निम्नवत् है-

(a) High Damage Risk Zone-IV.

(b) Moderate Damage Risk Zone-III

(c) Low Damage Risk Zone-II

2-उक्त तीनों वर्गीकरण में रखे गये जिलों की स्थिति निम्नवत् है-

(अ) High Damage Risk Zone-IV. में 16 जिले पूर्णतया आते हैं, जो कि निम्नवत् हैं-

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर एवं कुछ भाग निम्नलिखित जिलों का है-

पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, बहराइच, गोण्डा, मथुरा, अलीगढ़, बदायूं, संत कबीर नगर, देवरिया तथा बलिया।

(ब) Moderate Damage Risk Zone-III में 21 जिले पूर्णतया आते हैं-

सोनभद्र, चन्दौली, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, फैजाबाद, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, फर्रुखाबाद, एवं कुछ भाग निम्नलिखित जिलों का है—

मिर्जापुर, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, मथुरा, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया तथा बलिया।

(स) Moderate Damage Risk Zone-II में 7 जिले पूर्णतया आते हैं, जो निम्नवत् हैं—

ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, बांदा, कौशाम्बी, इलाहाबाद एवं कुछ भाग निम्नलिखित जिलों का है—

आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रतापगढ़ तथा मिर्जापुर।

3—उक्त क्रमांक-2 (i),(ii),(iii) में इंगित जिलों में भूकम्परोधी सुरक्षा उपायों के अन्तर्गत भवन निर्माण में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी—

(अ) भूतल सहित 3 मंजिल से अधिक अथवा 12.00 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के सभी प्रकार से भवनों पर भूकम्परोधी निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएँ लागू होंगी।

(ब) उपरोक्त प्रस्तर-1 में इंगित भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापनाओं के विकास हेतु भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, अन्य सुसंगत गाइडलाइन एवं अभिलेखों के प्रावधानों को शत प्रतिशत अपनाया जाना अनिवार्य होगा।

(स) भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराने के लिये वास्तुविदीय मानचित्र के साथ परिशिष्ट 1, 2, 3, व 4 में दिये गये प्रारूप अनिवार्य रूप से पूर्ण कर प्रस्तुत करेगा, उक्त प्रारूपों का जिला पंचायत के अधिकारी समुचित संज्ञान लेंगे।

(द) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फीट X 3 फीट आकार का एक बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामी का नाम आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे।

(i) नियम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

(ii) अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियां।

(iii) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नींव, सुपरस्ट्रक्चर की गणनाएँ एवं भवन को भू-कम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।

(iv) अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग्स जिनमें सेक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल होंगे।

(v) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी0एण्ड पी0का विवरण।

(vi) साईट इंजीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।

(vii) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।

## भाग-8

### विकसित एवं अविकसित जनपदों की सूची—(1)

इन उपविधियों के लिये फीस आदि निर्धारण के लिये उत्तर प्रदेश को (क) विकसित एवं (ख) अविकसित जनपदों में विभाजित किया गया है जो कि निम्नवत् हैं—

(क) लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न अन्य सभी जनपद।

## भाग-9

## भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे—

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू- आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची-(1) के जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5 (मीटर)	6 (मीटर)
1	आवासीय भवन— (i) भू-खंड 500 वर्ग मीटर तक (ii) भू-खंड 501-2000 वर्ग मीटर तक	80 65	3.00 4.00	15 15	15 15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन (i) व्यवसायिक केन्द्र, शापिंग माल्स, सुविधा (Convenient) शापिंग केन्द्र, होटल (ii) बैंक, सिनेमा मल्टीलप्लेक्स (iii) वेयर हाउस, गोदाम (iv) दुकाने व मार्केट	40 40 60 60	2.50 1.50 1.50 1.50	30 24 18 15	21 18 15 10
5	संस्थागत व शैक्षणिक भवन (i) समस्त उच्च शिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज आदि। (ii) हायर सेकेण्डरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि (iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	50 50 75	1.50 1.50 2.50	24 24 24	15 15 15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन (i) समुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन (ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल (iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	50 30 40 40	1.20 1.50 2.50 0.50	15 15 15 10	10 10 10 6

1	2	3	4	5	6
7	कार्यालय भवन				
	सरकारी, अर्द्धसरकारी, कार्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन काम्पलेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डैरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

## (2) सेट बैक (Set Back)

क्रमांक	भूखंड क्षेत्रफल (मीटर)	का (वर्ग (Front) मीटर)	साइड (Side) मीटर	पीछे (Reer) मीटर	लैण्ड स्कैपिंग (Landscaping) मीटर	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

## (3) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भूखण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

1	2	3
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हास्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रुम के लिए
7	हास्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

#### (4) भू-खण्ड का आकार एवं विद्यमान मार्ग की चौड़ाई

क्रमांक	भवन एवं भू-खण्ड उपयोग	न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	विद्यमान मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)
1	2	3	4
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	2000.00	9.0
2	रैन बसेरा (Night Selter)	500.00	6.0
3	औद्योगिक भवन	2000.00	9.0
4	व्यवसायिक भवन—		
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र	300.00	6.0
	(ii) शॉपिंग माल्स	2,500.00	9.0
	(iii) व्यावसायिक केन्द्र	2,500.00	9.0
	(iv) होटल	300.00	6.0
	(v) बैंक	300.00	6.0
	(vi) सिनेमा हॉल्स	2,500.00	9.0
	(vii) मल्टीप्लेक्स	2,500.00	9.0
	(viii) वेयर हाउस	2,500.00	9.0
	(ix) गोदाम	2,500.00	9.0
	(x) दुकानें व मार्केट	12 (प्रति दुकान)	6.0
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन—		
	(i) उच्च शिक्षण संस्थान	5,000.00	9.0
	(ii) विश्वविद्यालय	5,000.00	9.0
	(iii) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	5,000.00	9.0
	(iv) डिग्री कालेज आदि	5,000.00	9.0
	(v) हायर सेकेण्ड्री आदि	2,000.00	6.0
	(vi) प्राइमरी स्कूल	300.00	6.0

1	2	3	4
	(vii) क्रेच सेन्टर आदि	300.00	6.0
	(viii) हास्पिटल	500.00	9.0
	(ix) डिस्पेंसरी	300.00	6.0
	(x) चिकित्सालय	300.00	6.0
	(xi) लैब	300.00	6.0
	(xii) नर्सिंग होम आदि	500.00	9.0
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन—		
	(i) सामुदायिक केन्द्र	1,000.00	9.0
	(ii) क्लब	1,000.00	9.0
	(iii) बारात घर	1,000.00	9.0
	(iv) जिमखाना	1,000.00	9.0
	(v) अग्निशमन केन्द्र	1,000.00	9.0
	(vi) डाकघर	300.00	6.0
	(vii) पुलिस स्टेशन	1,000.00	6.0
	(viii) धर्मशाला	500.00	6.0
	(ix) लाज	300.00	6.0
	(x) अतिथिगृह	300.00	6.0
	(xi) हास्टल	1,000.00	6.0
	(xii) धर्मकांटा	800.00	9.0
	(xiii) पेट्रोल पम्प	500.00	9.0
	(xiv) गैस गोदाम	1,000.00	9.0
	(xv) शीत गृह	1,000.00	9.0
7	कार्यालय भवन—		
	(i) सरकारी	1,000.00	9.0
	(ii) अर्द्धसरकारी	1,000.00	9.0
	(iii) कारपोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	1,000.00	9.0
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन काल्प्लेक्स	4,000.00	9.0
9	शूटिंग रेंज	2,000.00	9.0
10	समाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	1,000.00	6.0
11	नर्सरी	800.00	6.0
12	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	2,000.00	9.0
13	फार्म हाउस	2,000.00	9.0
14	डेरी फार्म	1,000.00	6.0
15	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	1,000.00	6.0
16	ए0टी0एम0	...	...

**भाग-10****अग्निशमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस**

1-तीन मंजिल अथवा 12वर्ग मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा— संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन, हास्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6.0 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा, जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4.0 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2-अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.20 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी0, राईजर अधिकतम 19 सेमी0, एक फ्लाइंट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3-अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15.0 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

4-घुमावदार अग्नि निकास जीने की प्रावधान 10.0 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

5-उपरोक्त भवनों हेतु अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6-उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, (6)2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता, (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कर्नर सिस्टम आदि।

**भाग-11****इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी**

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाइन 33000 बोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

**भाग-12****शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सुविधाये प्रदान करने हेतु मानक**

**व्याप्ति प्रभाव**—उपविधियों का यह भाग सभी जन उपयोगी भवनों, सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर प्रभावी होगा परंतु समूह आवास, निजी व सरकारी आवासों पर लागू नहीं होगा।

1-भवन परिसर द्वार तथा भूतल पार्किंग से भवन के प्रवेश द्वार तक पथ समतल, सीढ़ियां रहित और न्यूनतम 1.80 मीटर चौड़ा होगा।

2-यदि कोई ढलान बनायी जाती है तो उसकी ढाल 5% से अधिक होगी।

3-फर्श निर्माण में ऐसी सामाग्री का इस्तेमाल किया जायेगा जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को भली-भांति प्रेरित या निर्देशित करने वाली हो।

4—धरातल फिसलन रहित होगा तथा उसकी बनावट ऐसी होगी जिस पर पहियेदार कुर्सी आसानी से चल सके, जो भी मोड़ बनाये जायेंगे, सामान्य धरातल के अनुरूप होंगे।

5—विकलांग व्यक्तियों के लिए वाहनों की पार्किंग हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जायेगी—

(अ) अशक्त व्यक्तियों के वाहनों के लिये परिसर प्रवेश के निकट दो कारों के लायक भूतल पार्किंग बनाया जायेगा जो भवन के प्रवेश द्वारा से 30 मीटर की पैदल दूरी पर होगा।

(ब) पार्किंग जगह की न्यूनतम चौड़ाई 3.60 मीटर होगी।

(स) उस स्थान के (पहियेदार कुर्सी प्रयोगकर्ताओं हेतु आरक्षित) होने की सूचना बड़े/साफ अक्षरों में लिखी जायेगी।

(द) पार्किंग स्थल पर ऐसा कोई संकेत या यंत्र लगाया जायेगा जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के मार्ग दर्शन हेतु ध्वनि सूचना देने वाले अथवा इसी प्रयोजन वाली कोई अन्य कोई व्यवस्था की जायेगी।

6—शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए भवन संबंधी संगत सुविधाएं निम्न प्रकार से होगी—

(अ) कुर्सीतल तक पहुंच मार्ग।

(ब) विकलांगों के लिये प्रवेश/निकाश द्वार को जोड़ने का गलियारा।

(स) सीढ़ी मार्ग।

(द) लिफ्ट।

(य) शैचालय।

(र) पेयजल।

### भाग—13

#### रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

1—भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा।

2—प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

### भाग—14

#### सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र हेतु कार्यवाही

1—निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर संयंत्र स्थापित किया जायेगा।

(अ) अस्पताल एवं नर्सिंग होम।

(ब) होटल।

(स) अतिथि गृह।

(द) विश्राम गृह।

(य) छात्रावास।

(र) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/प्राविधिक संस्थायें/प्रशिक्षण केंद्र।

(ल) सशस्त्र बल/अर्द्ध सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक।

(व) सामुदायिक केन्द्र, बैंकवेट हॉल, बारात घर तथा इसी प्रकार के उपयोग के अन्य भवन।

(श) 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन।

2—सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र एवं प्रणाली ब्यारो " ब्यारो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड" (B.I.S) विशिष्ट IS12933 के अनुरूप होनी चाहिये तथा जहाँ कहीं भी जब लगातार गर्म पानी की आवश्यकता हो, तो वहाँ सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ पानी गर्म करने हेतु बिजली अथवा अन्य व्यवस्था का प्राविधान किया जा सकता है।

#### भाग—15

##### सीवरेज का निस्तारण

**व्याप्ति प्रभाव—**स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल मूत्र तथा बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत, सुलतानपुर का इसके लिये कोई उत्तरदायित्व, व्यय अधिभार नहीं होगा।

#### भाग—16

##### नक्शे स्वीकृति की दरें (कृपया देखें भाग—8)

##### 1—आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन—

(अ) सूची—1(क) के अनुसार विकसित जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी

(ब) सूची—1 (ख) के अनुसार अविकसित जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 25.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

##### 2—व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन—

(अ) सूची—(1) (क) के अनुसार विकसित जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 100.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ब) सूची—1 (ख) के अनुसार अविकसित जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

3—(अ) **भूमि की प्लानिंग**—भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लानों में बांटना।

(ब) **भूमि विकास**— भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, बारात घर/बैंक्वेट हाल आदि।

(स) **भूमि का उपयोग**—भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन, आर0सी0सी0 पाइप आदि।

(द) **किसी परियोजना का ले आउट प्लान** (तलपट मानचित्र)

(अ) उपरोक्त 3 (A) से (D) तक सूची—(1) के अनुसार विकसित जनपदों में रुपये 20.00 प्रति वर्ग मीटर होगी। अन्य जनपदों में यह दर रुपये 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ब) उपरोक्त 3 (A) से (D) तक सूची—1(क) के अनुसार अविकसित जनपदों में रुपये 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

4—पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनर्निर्माण करने की दशा में अनुज्ञाशुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

5—स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

6—बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

7—यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी।

8—उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा भू-खण्ड विकसित करने पर या इन उपविधियों की किसी उपविधि/उपविधियों का उल्लंघन करने पर अर्थ—दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

9—पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने हेतु (सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर) दरें निम्नवत् लागू होंगी—

(अ) सूची-1(क) के अनुसार विकसित जनपदों में उक्त दरें रुपये 20.00 प्रति वर्गमीटर होंगी।

(ब) सूची-1(ख) के अनुसार अविकसित जनपदों में उक्त दरें रुपये 10.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

10—चार दीवारी/बाउण्ड्री वाल की स्वीकृति की दरें निम्नवत् होंगी—

(अ) सूची-1(क) के अनुसार विकसित जनपदों में उक्त दरें रुपये 10.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

(ब) सूची-1(ख) के अनुसार अविकसित जनपदों में उक्त दरें रुपये 5.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

**नोट:—**(शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

#### भाग-17

#### मोबाइल टावर्स की स्थापना

1—अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन पर टावर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

2—शैक्षणिक संस्थान, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन /स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

3—मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

4—आवेदन-पत्र की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त आवेदन-पत्र की एक छायाप्रति जिला अधिकारी एवं एक छायाप्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रथम सूचना के रूप में प्रेषित करनी होगी।

5—सेवा आपरेटर द्वारा टावर का निर्माण कार्य किय जाने से पूर्व काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पंजीकृत एवं अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है, (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर से अनाधिक होगा, भवन निर्माण उपविधियों के अंतर्गत है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी मानकों के आधार पर भवन की सुदृढ़ता के सम्बन्ध में अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के स्थान पर आई0आई0टी0 तथा इसके समकक्ष संस्थान लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि सरकारी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

6—टावर हेतु अनुज्ञा, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटर को ही प्रदान की जायेगी।

7—जनरेटर केवल Silent प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

8—यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3.0 मीटर ऊपर होना चाहिये।

9—जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

10—सेवा आपरेटर कंपनी और भवन स्वामी के संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।

11—सेवा प्रदाता द्वारा टावर में जनसामान्य का प्रवेश वर्जित करने के लिये समुचित उपाय यथा वायर फेंसिंग भवनों की छतों पर जाने वाले दरवाजों पर ताला आदि के प्रावधानों के साथ टावर परिसर के प्रवेश द्वार पर, उचित स्थान पर चेतावनी सूचक लाइन बोर्ड लगाना होगा जिसमें 'खतरा', 'आर0एफ0 विकिरण', 'कृपया प्रवेश न करें', लिखा होगा।

12—इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेल्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेशन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

13—अनुज्ञा-पत्र जारी करने की सूची-1(क) के अनुसार विकसित जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व सूची-1(ख) के अनुसार अविकसित जनपदों में पचास हजार रुपये जमा करने होंगे।

14—अनुज्ञा-पत्र के नवीकरण के लिये प्रथम बार लिये गये शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा कराना होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विकास शुल्क आदि नहीं लिया जायेगा।

#### भाग—18

##### अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1—स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2—ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी/कर अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3—कार्य अधिकारी /कर अधिकारी ऐसे प्राप्त ओवदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी /कर अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4—कार्य अधिकारी/कर अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5—अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु, निर्देशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6—अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7—अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय भवन एवं औद्योगिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा।

8—इन उपविधियों की प्रस्तावना एवं परिभाषाओं की मद संख्या 24, 28 व 29 में प्राप्त हर प्रकार के भवन के नक्शे एवं भू-खण्ड विकास के प्लान पर इस स्तर से आगे कार्यवाही करने से पूर्व निम्न कार्यवाही अनिवार्यतः की जायेगी—

(अ) यदि जिला पंचायत के जिला मुख्यालय में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का कार्यालय स्थित है तो उसके अधिशासी अभियंता को, या

(ब) यदि जिला पंचायत के जिला मुख्यालय में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषदका कार्यालय स्थित नहीं है तो लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को।

(स) नक्शे/प्लान प्रेषित किये जायेंगे एवं उनके प्राविधिक परीक्षण आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

**नोट**—उक्त अधिशासी अभियन्ताओं का तात्पर्य प्रस्तावना/परिभाषाओं की मद संख्या 15 (i) एवं (iv)के अनुरूप होगा।

9—अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अंतरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक माँग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

10—जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility) सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility) तकनीकी जाँच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

11—अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

12—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी/कर अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का माँग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

13—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा करना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

15—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की माँग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

**विवाद**—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद के होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा, जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश उभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

### भाग—19

#### सामान्य अनुदेश

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किमी० के दायरे में उपविधियोंनुसार निर्माण हेतु मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2—प्रस्तावित भू-खंड की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3-भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking), वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तलभण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल फ्लोर एरिया रेशियो एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

4-निकटतम हवाई अड्डा, चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो, के 5 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5-उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6-उपविधियों में दी गयी सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त, भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7-मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8-इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा, जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9-इन उपविधियों का पालन न करने की दशा में जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी-आर0पी0सी0 की धारा-133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

#### भाग-20

##### अनुज्ञा की शर्तें

1-अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि भवन निर्माण नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा उसके द्वारा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

2-अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियंता, जिला पंचायत की संस्तुति पर पंजीकृत वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा यथारूप स्वीकार कर दे।

3-पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अधीन कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

4-कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से, जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, उनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

#### भाग-21

##### दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत सुलतानपुर यह निर्देश देती है कि जो स्वामी इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा जो अंकन रु 1000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50.00 (पचास रुपये मात्र)

प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जायये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

एम0पी0 अग्रवाल,

आयुक्त,

अयोध्या मण्डल, अयोध्या।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 12 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 21, 1942 शक संवत्)

### भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

**कार्यालय, नगर पंचायत, लालगंज, प्रतापगढ़**

18 जून, 2020 ई०

सं० 177/न०प०लालगंज-उपविधि-विज्ञप्ति-2019 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के माध्यम से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 यू०पी० एक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 131 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत, लालगंज, प्रतापगढ़ ने नगर पंचायत की सीमान्तर्गत भवन कर व जल लगाने व वसूल करने की नियमावली तैयार की गयी है। जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगरवासियों व प्रभावित व्यक्ति/समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से नगर पंचायत, लालगंज को अवगत करा सकें।

समस्त नगरवासियों व प्रभावित व्यक्तियों/समूह से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 30 दिन के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगर पंचायत, कार्यालय को प्राप्त कराये। जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया सकें। समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, के संबंधित प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" व "हिन्दुस्तान" में दिनांक 23 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित कर आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। मा० बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 03, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 को सर्वसम्मति से अग्रेतर कार्यवाही हेतु अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव विनियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131(1) के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

**"भवन कर व जलकर" (शुल्क) उपविधि/नियमावली**

**1-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-**

- यह नियमावली नगर पंचायत, लालगंज, प्रतापगढ़ "भवन कर, जल कर लगाने व वसूल करने की नियमावली" वर्ष 2019 कही जायेगी।
- यह नियमावली नगर पंचायत, लालगंज, प्रतापगढ़ सीमान्तर्गत निहित सम्पत्ति पर लागू होगी।
- यह उपनियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

**2-परिभाषाएँ—**

जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, पर इस उपनियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) "अधिशाली अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत, लालगंज, प्रतापगढ़ के अधिशाली अधिकारी से है।

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत, लालगंज, प्रतापगढ़ के बोर्ड से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत, लालगंज, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत, लालगंज, प्रतापगढ़ से है।

(च) "नगर पंचायत की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) "भवन कर, जल कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में यथा परिभाषित भवन अथवा भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य से रोपित कर से है।

(ज) "स्वामी" से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति है जिसमें किसी भवन अथवा भूमि का वैधानिक रूप से मान्य स्वामित्व विहित हो।

(झ) "अध्यासी" से तात्पर्य उस व्यक्ति/संस्था से है जो उस भूमि अथवा भवन का किरायेदार हो या काबिज दाखिल।

(ञ) "भवन" का तात्पर्य गृह की परिभाषा में दुकानें मकान एवं उसका बरामदा (कच्चा एवं पक्का) सहन, दालान, कमरा तथा व्यवसाय उपयोग में आने वाले मकान, स्ट्रक्चर तथा उसकी संलग्न भूमि की चहारदीवारी सहित निर्माण माने जायेंगे।

(ट) "अनावासीय भवन" का तात्पर्य ऐसे किसी भवन या स्थान या भूमि या भवन या उसके भाग से है जो अनावासिक हो और जो उक्त अधिनियम की धारा के अधीन आच्छादित हो।

(ठ) "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 में अंकित परिभाषा से है।

**3-किसी भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्र का विवरण—**

(1) अधिशाली अधिकारी एक सूचना प्रकाशित करके भवन कर, जल कर, के भुगतान के लिये मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र 'क' और प्रपत्र 'ख' में यथास्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्र और अनावासिक भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रत्येक 5 वर्ष में एक विवरण, कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) अधिशाली अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिये प्रपत्र 'क' और 'ख' में विवरण प्रस्तुत करने के लिये नगर के विभिन्न वार्डों के लिये विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।

(3) जब कभी स्वामी या अध्यासी द्वारा स्वअध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाय या इसके विपरीत हो तो ऐसा होने के 60 दिन के भीतर स्वामी या अध्यासी के लिये प्रपत्र 'क' और 'ख' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

(4) जब किसी भवन में निर्माण या पुनः निर्माण के फलस्वरूप आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से 60 दिन के भीतर यथा स्थिति स्वामी या अध्यासी के लिये प्रपत्र 'क' और 'ख' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

**4-सम्पत्तियों का वर्गीकरण-**

(1) अधिशासी अधिकारी अधिनियम की धारा एवं उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्ड वार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात्-

(क) 12 मी0 से 24 मी0 से अधिक चौड़ाई वाला मार्ग

(ख) 03 मी0 से 12 मी0 से अधिक चौड़ाई वाला मार्ग

(ग) 03 मी0 से कम चौड़ाई वाला मार्ग

(2) अधिशासी अधिकारी अधिनियम की धारा एवं उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा-

(क) पक्का भवन आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित

(ख) अन्य पक्का भवन या

(ग) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो कि खण्ड 'क' और 'ख' से आच्छादित नहीं है।

(3) अधिशासी अधिकारी तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को 9 विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भू-खण्डों के मामलों में 3 विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा-

(क) भवन के मामलों में निम्नलिखित 9 समूह होंगे-

[एक] 12 मी0 से अधिक चौड़ाई वाला मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

[दो] 03 मी0 से 12 मी0 चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

[तीन] 03 मी0 से कम वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

[चार] 12 मी0 से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

[पांच] 03 मी0 से 12 मी0 चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

[छः] 03 मी0 से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

[सात] 12 मी0 से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

[आठ] 03 मी0 से 12 मी0 से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

[नौ] 03 मी0 से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि के मामले में निम्नलिखित तीन समूह होंगे-

[एक] 12 मी0 से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

[दो] 03 मी0 से 12 मी0 चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

[तीन] 03 मी0 से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

**5-न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण-**

(1) अधिशासी अधिकारी वार्ड के भीतर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार यथा स्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिये कारपेट एरिया के प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर की गणना करेगा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आवासिक भवन के रूप में दर नियत करेगा-

[एक] भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर, और

[दो] ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर

प्रतिबंध यह है कि ऐसे मासिक की दर नियत करने के पूर्व अधिशासी अधिकारी ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिये न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह भिन्न-भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई

की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिये प्राप्त आपत्तियां रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं अधिशासी अधिकारी द्वारा या अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय। आपत्तियों को बण्डलवार विनिश्चित किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण**—कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कारपेट एरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होंगी, जिन्हें स्वकर निर्धारण के लिये माना जायेगा।

(2) अनावासिक भवनों और भूमि की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उप नियम (1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है—

### अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1	2	3
1	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बैंक कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का पांच गुना
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र प्रयोगशालाएं नर्सिंग होम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
3	क्रीडा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमा गृह।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का दो गुना
4	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम के अधीन आच्छादित नहीं हैं	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान
5	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी डिपो और गोदाम आदि	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
6	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार वासगृह, जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का छः गुना
7	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब और इसी प्रकार के भवन	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
8	औद्योगिक इकाइयां, सरकारी, अर्द्ध सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
9	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0वी0 टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का चार गुना
10	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना

### 6—कर निर्धारण—

कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा—

(क) 1—आवासिक भवन के वार्षिक मूल्य की गणना—

कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति ईकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति ईकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12.80 प्रतिशत

(2) आवासिक भूमि की वार्षिक मूल्य की गणना—

भूमि का क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति ईकाई क्षेत्रफल मासिक किराया × 12

(ख) 1—अनावासिक भवनों की वार्षिक मूल्य की गणना—

आच्छादित क्षेत्रफल × आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर × 12

2—अनावासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना—

भूमि का क्षेत्रफल × आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर × 12

(ग) संदेय कर—अधिनियम की धारा 148 के अधीन नियत दरों के अनुसार वार्षिक मूल्य के आधार पर कर संदेय होंगे।

(घ) छूट—आवासिक भवनों के वार्षिक मूल्य में छूट अनुमन्य होगी और अधिनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार कर संदेय होंगे।

### टिप्पणी—

(1) भवनों और भूमियों के वार्षिक मूल्यांकन रु0 4,999.00 तक 12 प्रतिशत की दर से भवन कर तथा 10 प्रतिशत की दर से जल कर वार्षिक कर की दर से निर्धारण होगा।

(2) रु0 5,000.00 या उससे अधिक वार्षिक मूल्यांकन पर भवन कर, 15 प्रतिशत व जल कर 12 प्रतिशत की दर से निर्धारण होगा।

### 7—स्वनिर्धारण—

आवासिक भवन के विषय में भवन कर, जल कर, के भुगतान के लिये मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 6 और नियम 6-क के अनुसार कर निर्धारित करते हुये और नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के स्थान पर इस नियमावली के यथास्थिति प्रपत्र 'क' और प्रपत्र 'ख' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित बैंक/आनलाइन पोर्टल/किसी अन्य विकल्प में नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक यथास्थिति प्रपत्र 'क' या 'ख' और चालान के साथ कर जमा करेगा।

### 8—स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध—

उपनियम (6) के अधीन नियत दिनांक तक स्वनिर्धारण द्वारा भवन कर, जल करों के दायित्व का भुगतान पूर्व वर्ष के दायित्व की सीमा, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये, से अधिक नहीं होगी।

### 9—प्रोत्साहन—

अनावासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को यथास्थिति भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य में छूट प्रदान करते हुए निम्नलिखित रीति से प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव) दिया जा सकेगा—

(क) ऐसे भवन, जिसमें वर्षा जल संचयन या भूगर्भ जल संभरण की प्रणाली संस्थित हो और प्रचलन में हो या कम से कम क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत भाग वृक्षारोपण या हरियाली द्वारा आच्छादित हो या समुचित या पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो या व्यापार या विनिर्माण या ऐसे अन्य क्रियाकलापों में लगा हो जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता हो परन्तु प्रदूषणरोधी उपाय अपनाये गये हों, वार्षिक मूल्य में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुये प्रत्येक को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा:

परन्तु यह कि उपर्युक्त छूट इस खण्ड में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता और उनके उचित रख-रखाव का सत्यापन करते हुये वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान की जायेगी।

(ख) खण्ड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे भवनों के वार्षिक मूल्य में 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी यदि इस भवन में खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय न उपलब्ध कराये गये हों।

**10—कर निर्धारण सूची—**

(1) सभी भवनों या भू-खण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी—

(क) भूमि और भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'क', 'ख', 'ग' में और 'घ' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर,

या

(ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र यथास्थिति 'क' या 'ख' या 'ग' या 'घ' में सूचनायें न देने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर।

(ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे—

- (1) सड़क या मोहल्ले जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम;
- (2) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट द्वारा जो पहचान के लिये पर्याप्त हो, सम्पत्ति का अभिधान;
- (3) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम;
- (4) भवन या भूमि के समूह के लिये कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर;
- (5) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों;
- (6) भवन निर्माण का वर्ष;
- (7) भवन निर्माण की प्रकृति।

**11—स्वकर निर्माण के सम्बन्ध में सूची—**

ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'क' पर और अनावासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'ख' पर विहित अवधि के भीतर स्वानिर्धारित कर जमा करा दिया गया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा, परन्तु नियम 10 के उपबन्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

**12—स्वकर निर्धारण—**

किसी भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिये मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भवन कर, जल कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित भवन कर, जल कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।

**13—**(1) यदि कई भवन एक ही चहारदीवारी अर्थात् हाता में हो तो प्रत्येक भवन का पृथक् नं0 तथा वार्षिक मूल्यांकन होगा।

(2) यदि एक भवन के कुछ भाग में भवन स्वामी तथा कुछ भाग किरायेदारी पर है तो ऐसी स्थिति में स्वयं निवासित भाग का अलग तथा वास्तविक किरायेदारी का अलग विवरण लिखकर वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जायेगा। भवन स्वामी/अध्यासी की प्रार्थना पर वार्षिक मूल्य टेनामेन्ट्स (अलग-अलग) से निर्धारण किया जायेगा।

**14—भवन कर, जल कर जमा की अवधि—**

(1) भवन कर, जल कर प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में देय होगा। बिल न प्राप्त होने पर 30 सितम्बर, तक अथवा बिल प्राप्ति के 15 दिन के भीतर सम्पूर्ण भुगतान करने की दशा में केवल जारी वर्ष के करों में 10 प्रतिशत तक की छूट देय होगी। 30 सितम्बर, तक की छूट की दरों की घोषणा अन्तिम तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व प्रशासक/अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(2) यदि 30 सितम्बर, के पश्चात् बिल प्राप्त कराये जाते हैं तो 30 सितम्बर, तक की छूट की अधिकतम घोषणा का 50 प्रतिशत छूट निर्धारित अवधि में भुगतान पर देय होगी।

(3) 31 मार्च, तक भुगतान प्राप्त न होने की दशा में समस्त कर धनराशि पर 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ ठीक अगली प्रथम अप्रैल से देय होगा। प्रत्येक वर्ष विलम्ब शुल्क की गणना केवल करों के अवशेष पर होगी, कुल मांग योग पर प्रत्येक वर्ष का विलम्ब शुल्क, यदि हो की गणना अलग से होगी।

(4) मूल्यांकन सूची में अंकित भवन स्वामी/अध्यासी के नाम से जारी मांग बिल (करों) का भुगतान नहीं करता है और स्वयं भवन में नहीं रहता है ऐसी स्थिति में भवन कर काबिज (किरायेदार)/अध्यासी को नोटिस देकर वसूल की जायेगी।

(5) मूल्यांकन सूची अथवा उसके किसी भाग की नकल नियमानुसार शुल्क जमा करने पर दी जायेगी।

(6) भवन का स्थानान्तरण रजिस्ट्री/वसीयत/हिवा/दान/उपहार/विरासत आदि कारणों से होता है तो स्थानान्तरण हेतु की गयी कार्यवाही स्वामी की मृत्यु की तिथि से 90 दिन के अन्दर सूची नामान्तरण कराने हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप जिसका मूल्य रु0 10.00 होगा, नगर पंचायत, लालगंज में दिया जायेगा। 90 दिन के बाद 9 माह तक विलम्ब शुल्क रु0 25.00 देय होगा। इस अवधि के पश्चात् प्रत्येक वर्ष का विलम्ब शुल्क रु0 20.00 देय होगा।

#### 15-भवन कर/जल कर से छूट भवनों एवं भूमियों का विवरण-

(1) वे भवन/भूमि जिनका वार्षिक मूल्य रु0 360.00 या उससे कम है भवन कर, जल कर से मुक्त होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि भवन स्वामी/अध्यासी का उक्त भवन के अतिरिक्त नगर में अन्य कोई भवन अथवा भूमि नहीं होनी चाहिये। नगर पंचायत के संतुष्ट होने पर करों की मुक्ति साल व साल देय होगी।

(2) वे भवन/भूमि जिनसे नगर पंचायत की पानी पाइप लाइन व हैण्डपम्प 200 मी0 की परिधि से अधिक दूरी पर है। जलकर से मुक्त होंगे।

(3) वे भवन कर, जल कर से मुक्त होंगे-

[अ] सार्वजनिक पूजा उपासना के रूप में उपयोग होते हैं।

[ब] धर्मशाला जिसमें तीर्थ पर जाने वाले यात्री ठहरे और ठहरने के एवं में कोई भुगतान न करें।

[स] मान्यता प्राप्त पुस्तकालय, कब्रिस्तान/शमशान घाट।

[द] कोर्ट, कोषागार, सरकारी असलहा खाना, जेल (कार्यालयों को छोड़कर)।

[य] मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाएँ, छात्रावास (कार्यालय को छोड़कर)।

[र] सार्वजनिक क्रीडास्थल-(कार्यालय, आवासीय स्थान, कैन्टीन को छोड़कर)।

[ल] भवन जो नगर पंचायत के स्वामित्व के हों।

[व] विशेष परिस्थितियों में भवन स्वामी/अध्यासी के आग्रह पर प्रशासक/बोर्ड के संतुष्ट होने की दशा में एक वर्ष का भवन कर से मुक्त कर सकता है। एक वर्ष की अधिक बकाया की दशा में शासन की अनुमति/मार्गदर्शन लिया जायेगा।

[श] वे भवन जो केवल नगर पंचायत के कर्मचारियों के नाम हों तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन नगर पंचायत लालगंज द्वारा देय हो, भवन कर एवं जल कर से पेंशन अवधि तक मुक्त होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि कर्मचारी पेंशन प्राप्तकर्ता का नगर में एक से अधिक अन्य भवन या भूमि न हो तथा भवन आंशिक अथवा पूरा किरायेदारी पर न हो।

16-इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के बारे में विहित प्राधिकारी/आयुक्त यदि संतुष्ट है कि उक्त विधि के किसी प्राविधान का दुरुपयोग नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है तो उक्त प्राविधानों को निलम्बित करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकारी विहित प्राधिकारी/आयुक्त होगा।

**शास्ति**

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, लालगंज प्रतापगढ़ यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि बार-बार अपराध किया जा रहा है तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

**प्रपत्र 'क'****अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में भवन कर, जल कर स्व-निर्धारण प्रपत्र****1—स्वामी/अध्यासी का विवरण—**

- (1) स्वामी/अध्यासी का नाम—.....
- (2) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम—.....
- (3) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता—.....
- (4) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता—.....
- (5) अन्य विवरण, यदि कोई हो—.....

**2—भवन या भूमि सम्बन्धी ब्यौरा—**

- (1) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)—.....
- (2) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)—.....
- (3) अन्य विवरण, यदि कोई हो—.....

**3—अवस्थिति का विवरण—****(क) भवन या भूमि अवस्थित है—**

- [1] 12 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- [2] 03 मीटर से 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- [3] 03 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

**(ख) भवन निर्माण की प्रकृति**

(एक) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित

(दो) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाइबर या टीनशेड

(तीन) कच्चे भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं।

**टिप्पणी—**कृपया प्रयोज्य खाने में सही का निशान लगायें।

4—भवन निर्माण का वर्ष.....

5—पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

6—वार्षिक मूल्य की गणना.....

(क) भवन का वार्षिक मूल्य.....

[एक] अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराया का मासिक दर

[दो] नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक

[तीन] भवन हेतु प्राप्त किराये का मासिक दर ((एक) X (दो))

[चार] भवन का आच्छादित क्षेत्रफल.....

[पांच] भवन का वार्षिक मूल्य=किराये की मासिक दर X आच्छादित क्षेत्रफल X 12 [(तीन) X (चार) X 12]

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य.....

[एक] अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भूमि हेतु नियत किराया का मासिक दर

[दो] नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक

[तीन] भूमि (एक) X (दो) के लिये प्राप्त किराये का मासिक दर

[चार] भूमि का क्षेत्रफल.....

[पांच] भूमि का वार्षिक मूल्य=किराये की मासिक दर X आच्छादित क्षेत्रफल X 12 (तीन) X (चार) X 12)

(ग) कुल वार्षिक मूल्य = क (पांच) + ख (पांच)

7-कर की गणना-

यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X सामान्य कर की दर

(एक) सामान्य कर-----

100

यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X जल कर की दर

(दो) जल कर-----

100

यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X मल नाली कर की दर

(तीन) मल नाली कर-----

100

यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X कर की दर

(चार) अन्य कर-----

100

8-जमा किये गये कर का विवरण-

क्र०सं०	कर का नाम	कर की धनराशि	चालान/प्राप्ति सं०	दिनांक	बैंक/कार्यालय का नाम
---------	-----------	--------------	--------------------	--------	----------------------

#### सत्यापन

मैं.....वार्ड सं०.....के मोहल्ला.....में स्थित भवन सं०..... का स्वामी/अध्यासी एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक.....

## प्रपत्र 'ख'

## आवासिक भवनों के सम्बन्ध में भवन कर, जल कर स्व-निर्धारण प्रपत्र

## 1-स्वामी/अध्यासी का विवरण-

- (1) स्वामी/अध्यासी का नाम-.....
- (2) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम-.....
- (3) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता-.....
- (4) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता-.....
- (5) अन्य विवरण, यदि कोई हो-

## 2-भवन या भूमि सम्बन्धी ब्यौरा-

- (1) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)-.....
- (2) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)-.....
- (3) अन्य विवरण, यदि कोई हो-.....

## 3-अवस्थिति का विवरण-

## (क) भवन या भूमि अवस्थित है-

- [1] 03 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- [2] 03 मीटर से 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- [3] 03 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

## (ख) भवन निर्माण की प्रकृति-

- (एक) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित
- (दो) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाइबर या टीनशेड
- (तीन) कच्चे भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं।

टिप्पणी-कृपया प्रयोज्य खाने में सही का निशान लगायें।

## 4-भवन निर्माण का वर्ष.....

## 5-पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

## 6-वार्षिक मूल्य की गणना.....

## (क) भवन का वार्षिक मूल्य.....

- [एक] अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराया का मासिक दर
- [दो] नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक
- [तीन] भवन हेतु प्राप्त किराये का मासिक दर (एक) X (दो)
- [चार] भवन का आच्छादित क्षेत्रफल.....

[पांच] भवन का वार्षिक मूल्य=किराये की मासिक दर X आच्छादित क्षेत्रफल X 12  
(तीन) X (चार) X 12)

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य.....

[एक] अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भूमि हेतु नियत किराया का मासिक दर

[दो] नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक

[तीन] भूमि (एक) X (दो) के लिये प्राप्त किराये का मासिक दर

[चार] भूमि का क्षेत्रफल.....

[पांच] भूमि का वार्षिक मूल्य=किराये की मासिक दर X आच्छादित क्षेत्रफल X 12 (तीन) X (चार) X 12)

(ग) कुल वार्षिक मूल्य = क (पांच) + ख (पांच)

7-कर की गणना-

यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X सामान्य कर की दर

(एक) सामान्य कर-----

100

यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X जल कर की दर

(दो) जल कर-----

100

यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X मल नाली कर की दर

(तीन) मल नाली कर-----

100

यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X कर की दर

(चार) अन्य कर-----

100

8-जमा किये गये कर का विवरण-

क्र०सं०	कर का नाम	कर की धनराशि	चालान/प्राप्ति सं०	दिनांक	बैंक/कार्यालय का नाम
---------	-----------	--------------	--------------------	--------	----------------------

#### सत्यापन

मैं.....वार्ड सं०.....के मोहल्ला.....में स्थित भवन सं०..... का स्वामी/अध्यासी एतद्वारा घोषित करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक.....

स्वामी/अध्यासी का नाम

व हस्ताक्षर।

## प्रपत्र 'ग'

## आवासिक भवन के सम्बन्ध में भवन कर, जल कर निर्धारण प्रपत्र

## 1—स्वामी/अध्यासी का विवरण—

- (1) स्वामी/अध्यासी का नाम—.....
- (2) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम—.....
- (3) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता—.....
- (4) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता—.....
- (5) अन्य विवरण, यदि कोई हो—

## 2—भवन या भूमि सम्बन्धी विवरण—

- (1) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)—.....
- (2) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)—.....
- (3) अन्य विवरण, यदि कोई हो—.....

## 3—अवस्थिति का विवरण—

## (क) भवन या भूमि अवस्थित है—

- [1] 12 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- [2] 03 मीटर से 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- [3] 03 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

## (ख) भवन निर्माण की प्रकृति—

- [1] पक्का भवन, आर0सी0छत या आर0बी0 छत सहित
- [2] अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाइबर या टीनशेड
- [3] कच्चे भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

**टिप्पणी—**कृपया प्रयोज्य खाने में सही का निशान लगायें।

4—भवन निर्माण का वर्ष.....

5—पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

## सत्यापन

मैं.....वार्ड सं0.....के मोहल्ला.....में स्थित भवन सं0..... का स्वामी/अध्यासी एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक.....

## प्रपत्र 'घ'

## अनावासिक भवन के सम्बन्ध में भवन कर, जल कर निर्धारण प्रपत्र

## 1-स्वामी/अध्यासी का विवरण—

- (1) स्वामी/अध्यासी का नाम—.....
- (2) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम—.....
- (3) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता—.....
- (4) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता—.....
- (5) अन्य विवरण, यदि कोई हो—.....

## 2-भवन या भूमि सम्बन्धी विवरण—

- (1) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)—.....
- (2) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)—.....
- (3) अन्य विवरण, यदि कोई हो—.....

## 3-अवस्थिति का विवरण—

(क) भवन या भूमि अवस्थित है—

- [1] 03 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- [2] 03 मीटर से 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- [3] 03 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन निर्माण की प्रकृति—

- [1] पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित
- [2] अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाइबर या टीनशेड
- [3] कच्चे भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

टिप्पणी—कृपया प्रयोज्य खाने में सही का निशान लगायें।

4-भवन निर्माण का वर्ष.....

5-पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

## सत्यापन

मैं.....वार्ड सं0.....के मोहल्ला.....में स्थित भवन सं0..... का स्वामी/अध्यासी एतद्वारा घोषित करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्योरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक.....

नाम.....

पदनाम.....

हस्ताक्षर.....

अनीता द्विवेदी,  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत, लालगंज,  
प्रतापगढ़।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, जनपद देवरिया

21 जुलाई, 2020 ई0

सं0 1084/2020 न0पा0परि0 (2020-2021)—उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 ज, ख के अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद् के प्रस्ताव संख्या 5/6, दिनांक 02 मार्च, 2019 द्वारा नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज विविध व्यवसायों/दुकानों गतिविधियों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क लागू किये जाने के सम्बन्ध में उपविधि पारित कर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, के अनुक्रम में लाईसेन्स व अन्य शुल्क उपनियम का प्रकाशन कराया गया, जिसमें निर्धारित अवधि तक कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने पर नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज की बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 2/4, दिनांक 17 जनवरी, 2020 द्वारा उपनियम लागू करने का फाइनल निर्णय लिया गया। यह उपनियम राजकीय गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

**परिभाषाएँ**—विषय के प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में—

- (क) यह उपनियमावली नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया की लाईसेन्सिंग नियन्त्रण उपनियमावली कहलायेगी।
- (ख) “अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया के अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी से है।
- (ग) “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य अधिशाली अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया के अधिशाली अधिकारी से है।
- (घ) “प्रभारी अधिकारी” का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, जनपद देवरिया के प्रभारी अधिकारी से है।
- (ङ) “लाईसेन्सिंग अधिकारी” का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, जनपद देवरिया के लाईसेन्सिंग अधिकारी से है।

### उपनियम

- 1—यह उपनियम नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, जनपद देवरिया के सीमान्तर्गत लागू होता है।
- 2—यह उपनियम लाईसेन्सिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी उपनियम कहलायेगी।
- 3—यह उपनियम विहित प्राधिकारी की स्वीकृति के तुरन्त बाद लागू होगा।
- 4—इस उपनियम के अन्तर्गत कोई भी दुकानदार व अन्य व्यवसायी लाईसेन्स प्राप्त किये बिना अपनी दुकान/व्यवसाय नहीं चला सकेगा एवं इस उपनियम के लागू होने के पूर्व चल रहे समस्त दुकान/व्यवसाय का लाईसेन्स दुकानदार/व्यवसायी को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5—इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाईसेन्स की अवधि एक वित्तीय वर्ष की होगी जो 01 अप्रैल से लागू हो 31 मार्च को समाप्त होगी।
- 6—प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को पालिका द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शुल्क की धनराशि को अदा करके लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 7—दुकानदार/व्यवसायी को लाईसेन्स प्राप्त करने के लिये अपेक्षित धनराशि कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज में जमा कर अथवा पालिका कार्यालय द्वारा अधिकृत कर्मचारी को जमा करके रसीद प्राप्त कर सकता है।

8—दुकानदार/व्यवसायी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बॉटों का मापों में प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

9—इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाईसेन्स केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य किसी विधिक संस्था द्वारा पालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु प्राप्त लाईसेन्स से भिन्न होगा।

10—कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी छुआ-छूत की बीमारी से ग्रस्त है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा एवं ऐसे व्यक्ति को उल्लिखित व्यवसायों में सहायक अथवा नौकर भी रखने का अधिकारी नहीं होगा।

11—नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया के अध्यक्ष/प्रशासक/अधिकासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाईसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी लाईसेन्स दिखाने के लिये बाध्य होंगे तथा प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।

12—अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया के द्वारा लाईसेन्स निर्गत किया जायेगा।

13—जो शुल्क तालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाईसेन्स शुल्क लिया जायेगा।

14—इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व में प्रभावी फैक्ट्री/दुकान/वाहन लाईसेन्स उपनियमावली की शुल्क की दरें स्वतः निरस्त हो जायेंगी।

15—वाहन के लाईसेन्स न बनाने अथवा चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर इसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा वाहन बन्द किये जा सकते हैं तत्पश्चात् 15 दिन में लाईसेन्स न बनवाने पर लाईसेन्स अधिकारी द्वारा उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी करायी जा सकती है।

16—उपनियमों में संशोधन पालिका बोर्ड किसी भी समय कर सकता है एवं शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्गत किये जा सकते हैं।

17—वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माह अप्रैल, मई व जून में दुकानदार/व्यवसायी द्वारा लाईसेन्स बनवाने पर पालिका द्वारा प्रत्येक लाईसेन्स पर 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

18—वित्तीय वर्ष के माह-जून तक प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को लाईसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा अन्यथा वसूली प्रतिमाह रु0 50.00 विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

19—दुकानदार/व्यवसायी द्वारा लाईसेन्स शुल्क वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर जमा नहीं करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति करायी जायेगी।

20—नगरपालिका बोर्ड/शासनादेश के निर्णयानुसार लागू लाईसेन्स शुल्क में आवश्यक वृद्धि की जा सकती है।

21—दुकानदार/व्यवसायी अपना व्यवसाय/दुकान चाहे अपने निजी मकान/दुकान/खुले जमीन अथवा किराये के मकान/दुकान/खुले जमीन पर कर करता है, उसे अपने दुकान/व्यवसाय के अनुरूप लाईसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा।

22—सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी लाईसेन्स को किसी भी समय निरस्त कर सकता है अथवा उचित नहीं होने पर लाईसेन्स देने से इन्कार करने का अधिकार होगा।

## नगरपालिका बोर्ड द्वारा निर्धारित लाईसेन्स शुल्क की वार्षिक दरों का विवरण

क्र० सं०	दुकान/व्यवसाय का नाम	लाईसेन्स हेतु निर्धारित दरें
1	2	3
		रु०
1	पाँच सितारा होटल	12,000.00
2	तीन सितारा होटल	9,000.00
3	होटल/लाजिंग/गेस्ट हाउस (10 बेड तक)	900.00
4	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	3,000.00
5	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड तक)	1,500.00
6	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
7	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड तक)	2,000.00
8	प्राइवेट अस्पताल (बिना ऑपरेशन)	1,000.00
9	प्राइवेट अस्पताल (ऑपरेशन युक्त)	1,500.00
10	एक्स-रे क्लीनिक	1,500.00
11	पैथालोजी सेन्टर	500.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	1,000.00
13	आटो रिक्शा 7 सीटर	500.00
14	आटो रिक्शा 4 सीटर	250.00
15	आटो रिक्शा/ई-रिक्शा 2 सीटर	150.00
16	बस	1,500.00
17	मिनी बस	1,000.00
18	तांगा	30.00
19	रिक्शा किराये पर चालित	100.00
20	रिक्शा निजी चालित	50.00
21	रिक्शा चालक शुल्क	20.00
22	ठेला	75.00
23	हाथ ठेला	20.00
24	टाली मशीन चालित	100.00
25	अन्य चार पहिया व्यापारिक वाहन	750.00

1	2	3
		रु0
26	धुलाई गृह लान्ड्री	500.00
27	झाई क्लीनर	1,000.00
28	फाईनेन्स कम्पनी	10,000.00
29	इंश्योरेन्स कम्पनी	15,000.00
30	फाउंडिंग इण्डस्ट्रीज	500.00
31	पशु स्लाटर हाउस (प्रति पशु)	10.00
32	हड्डी/खाल/बाल गोदाम	1,000.00
33	बीयर बार/बीयर दुकान	4,500.00
34	देशी मदिरा की दुकान	6,000.00
35	विदेशी मदिरा की दुकान	12,000.00
36	आईस्क्रीम फैक्ट्री	1,000.00
37	बिल्डर्स रजिस्टर्ड	4,000.00
38	भैंसा मांस दुकान	300.00
39	बकरा मांस दुकान	400.00
40	पशु पालन (प्रति पशु)	10.00
41	कांजी हाउस में बंद जानवरों पर जुर्माना	350.00
42	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर	25.00
43	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर	15.00

### दण्ड

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुये यह निर्देश दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों के किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करने में प्रोत्साहित करेगा उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो इस उपनियम में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुना से दस गुना तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से या प्रमाणित हो जाने पर की अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है एवं जुर्माना के साथ-साथ तीन मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),

अध्यक्ष,

नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज,

जनपद देवरिया।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, जनपद देवरिया

21 जुलाई, 2020 ई0

सं0 1085/2020 न0पा0परि0 (2020-2021)—नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1) व 126(10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया की सीमा में स्थित सभी मकानों, इमारतों तथा भूमियों पर गृहकर निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या प्र0स0408/नौ-10-63ल/95टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9, दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगर सीमान्तर्गत भवनों तथा सम्पत्तियों का कर निर्धारण (गृहकर/जलकर) लिये जाने हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी तथा सम्पत्तियों पर स्वतः कर निर्धारण नियमावली वर्ष, 2019 बनाये हैं, जो राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू होगी।

### नियमावली

1—यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया की सीमा में स्थित भवनों तथा सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019 कही जायेगी।

2—यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया की सीमा में लागू होगी।

3—यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् इसी वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू होगी।

4—“नगरपालिका” का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया से है।

5—“अधिकासी अधिकारी” का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया के अधिकासी अधिकारी से है।

6—“प्रशासक/बोर्ड” का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया के प्रशासक/बोर्ड से है।

7—“अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी” का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी से है।

8—“अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

9—“शासनादेश का तात्पर्य उ0प्र0 शासन के आदेशों/निर्देशों से है।

10—कोई भी व्यक्ति यदि नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया की सीमा में भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर निर्धारण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेंगे। इसके लिए नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया से एक आवेदन-पत्र (प्रपत्र “क” और “ख”) प्राप्त कर अपने मकान का ब्योरा देकर उपविधि में दी गयी निर्धारित दर के अनुसार स्वकर का निर्धारण करेंगे।

11—आवेदन-पत्र (प्रपत्र “क” और “ख”) नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

12—जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया द्वारा की जायेगी।

13—**भवन**—इसमें वह सभी अहाते, उप घर आदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित है तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर को भूमि सहित भवन कहा जायेगा और मकान का तात्पर्य सं0प्रा0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा में अंकित परिभाषा से है।

14—“सम्पत्ति” का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है।

15—“आच्छादित क्षेत्रफल” का तात्पर्य कुर्सी के ऊपर जिसपर भवन निर्मित है, के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

16—कारपेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जायेगी—

(क) कमरे—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ख) आच्छादित बरामदा—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ग) बालकनी, कैरीडोर, रसोई व भण्डार गृह—आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप होगा।

(घ) गैरज—आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप।

(ङ) स्नान गृह, शौचालय, पोर्टिको, जीने से आच्छादित क्षेत्र—कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

अथवा

कारपेट एरिया—आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत भाग।

17—कर का निर्धारण—कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा :

(क) वार्षिक मूल्य की गणना, वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12।

18—(क) **करों का भुगतान**—अधिशाली अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी बनाये गये नियम के अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज कार्यालय अथवा उसके द्वारा अभिसूचित बैंक में कर का भुगतान किया जायेगा। गृहकर निर्धारण का भुगतान का सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि के नियमावली में दी गयी शास्ति तथा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173 (क) के अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा 173(क) की कार्यवाही का खर्च तथा बकाया धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा।

(ख) यह है कि नगरपालिका की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी जैसे भी परिस्थिति हो को नगरपालिका की अधिनियम की धारा 158 (1)(2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उनके सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) इस उपविधि के किसी भी प्रावधान के बारे में नगरपालिका यदि संस्तुष्ट है कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरुपयोग परिषद् द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्रावधान/नियमानुसार जनहित में नहीं है, तो उक्त प्रावधान को निरस्त करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार नगरपालिका को होगा।

**19—स्वतः अध्यासित भवनों के लिये छूट—**

- (क) 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के लिये वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (ख) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (घ) व्यावसायिक/औद्योगिक, भूमि/भवन होने की दशा में कोई भी छूट अनुमन्य नहीं होगी।

**20—किराये पर उठे आवासीय भवनों का उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य से (ARV) जोड़ें :**

- क—दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक होगा (+) 25 प्रतिशत
- ख—दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा (+) 12.5 प्रतिशत
- ग—बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो यथावत समझा जायेगा।

**नोट**—नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (2) में यह प्रावधान है कि जहां नगरपालिका किराये में किसी कारण से असाधारण परिस्थितियों में किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो अत्यधिक हो वहां नगरपालिका परिषद् किसी भी धनराशि पर जो भी न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

**21—व्यावसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य**—सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम, बेकरी, आटा चक्की, कोयला, लकड़ी, कृषि उपकरणों के लिये केन्द्र, शीतगृह, रिजोर्ट, होटल व बेवसाईट व आटोमोबाईल शोरूम/सर्विस सेन्टर व भोजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0 पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस अधिष्ठान भण्डारण तथा गोदाम, निजी कार्यालय, बैंक व अन्य अनावासीय भवनों से है।

**22—औद्योगिक सम्पत्तियों से तात्पर्य**—सेवा/कुटीर उद्योग, औद्योगिक कारखाने, पावरलूम कारखाना, सूचना प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी/एल0पी0जी0 व फीलिंग प्लान्ट/संयन्त्र/केन्द्र आदि से है।

**23—इन्स्टीट्यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य**—राजकीय, अर्द्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द्र/पी0ए0सी0 पुलिस लाईन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र, अतिथि गृह, निरीक्षण गृह, धर्मशाला, रैनबसेरा, लाजिंग, बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागार हैण्डिकैप, चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह एवं देखभाल केन्द्र, वृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक शैक्षिक संस्थान, उच्च माध्यमिक इण्टर/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इन्जिनियरिंग, विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, आई0टी0आई0, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र, पुस्तकालय/वाचनालय, नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र, सिलाई केन्द्र, बुनाई कढ़ाई केन्द्र, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि, आडियोटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, योग, सामुदायिक केन्द्र, धार्मिक केन्द्र, बारातघर, कान्फ्रेंस एवं मीटिंग हाल, प्रदर्शनी केन्द्र, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

**नोट**—जो भी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक संस्थाएं निःशुल्क जनहित में कार्य कर रही हैं वे कर से मुक्त होंगी। परन्तु जिस धार्मिक/राजनैतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा उस पर कर देय होगा।

**24—रेन्ट कन्ट्रोल के मकान**—रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज देवरिया प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होगा बल्कि गृहकर का निर्धारण उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04, नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार किया जायेगा।

25—जिन भवनों/व्यावसायिक भवनों में भवन स्वामी का पता नहीं चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को ही गृहकर का भुगतान करना होगा।

#### 26—करों में छूट—

(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी, 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य कर जमा कर दिये जाने की दशा में 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी, इसके पश्चात कर जमा करने पर कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) सम्बन्धित वर्ष में कर जमा नहीं करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में गृहकर पर 10 प्रतिशत सरचार्ज की दर से देय होगा।

27—सम्बन्धित संसूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर नगरपालिका कार्यालय में भरकर जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पूर्ण विवरण होने की दशा में स्वामी अध्यासी से सम्पत्ति की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने धनराशि शास्ति (जुर्माना) के रूप में ली जायेगी निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 50 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भू-खण्ड पर क्रमशः रु0 100/500/1000/3000 तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति (जुर्माना) का 5 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।

28—भवन किराये पर देने या रिक्त होने, भवन में निर्माण/पुनर्निर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) में वृद्धि होने पर तथा भवन के व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र (ख) में ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

29—जिन भवनों/भूमियों को नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र “क” और “ख” पर उपरोक्तानुसार सूचना भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र “क” के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया भी जमा करेंगे।

30—(क) मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी—कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में करदाता सूची में अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करते हुए विचाराधीन है तो उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा अन्यथा उसके बाद सूची में आवेदन के अनुसार नाम कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

(ख) गृहकर पंजिका में दर्ज ऐसी भूमि/भवन जो पालिका के स्वामित्व की भूमि है जो किसी कारण वश निजी उपयोग में लायी जा रही है तो वह गृहकर पंजिका में स्वतः निरस्त/कर मुक्त मानी जायेगी।

#### 31—मकानों का हस्तान्तरण सम्बन्धी नियम—

(क) यदि किसी भवन या भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तान्तरित होता है तो स्वामित्व हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वामित्व पाने वाला व्यक्ति ऐसे संस्था ऐसे हस्तान्तरण के 03 माह के अन्दर उसकी सूचना पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर लिखित सूचना रु0 300.00 शुल्क जमा करके अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(ग) यदि किसी करदाता अथवा भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देने में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय उसे नामान्तरण शुल्क के साथ रु0 100.00 विलम्ब शुल्क भी देय होगा तभी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही किया जायेगा। यही प्रक्रिया विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही पर भी लागू होगी।

(घ) विक्रय-पत्र के आधार पर आवेदक नगरपालिका अभिलेखों में नाम दर्ज कराना चाहता है तो उसका शुल्क रु0 500.00 जमा करने के बाद ही कार्यवाही शुरू की जायेगी।

32-कर निर्धारण दर-गृहकर वार्षिक मूल्य का 05 प्रतिशत देय होगा।

33-(1) किसी भी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवन जो 30 वर्ग मी0 के माप वाले या 15 वर्ग मी0 तक कारपेट क्षेत्रफल वाले भूखण्ड पर निर्मित हो उसके स्वामी के स्वामित्व में नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज के सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन/भूखण्ड न हो पर वार्षिक मूल्य की गणना नहीं की जायेगी वो कर से मुक्त होंगे।

(2) यदि आंशिक भाग का उपयोग व्यावसायिक/औद्योगिक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और आंशिक भाग पर निवासित है तो व्यावसायिक/औद्योगिक वाले भाग पर व्यावसायिक/औद्योगिक दर लागू होगा तथा निवासित भाग पर निवसित दर लागू होगा।

(3) व्यावसायिक/औद्योगिक उपयोग वाले आवासों/आवासीय अंशों पर कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासीय भवन की मासिक किराये की दर
1	2	3
1	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का प्रतिष्ठान बैंक, कार्यालय, होटल कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान पांच गुना (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर) आवासीय सह दुकान की स्थिति में	
2	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0बी0 टावर, दूर संचार या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का चार गुना
3	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पॉली क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंग होम, चिकित्सालय केन्द्र, मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
4	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
5	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, शादी/बारात घर, क्लब व इसी प्रकार के भवन	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना

1	2	3
6	औद्योगिक इकाइयां, सरकारी, अर्धसरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
7	क्रीड़ा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर तथा सिनेमा घर	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का दो गुना
8	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
9	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 129-क के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर के समान

नगरपालिका सीमान्तर्गत निर्धारित परिधि में जलापूर्ति पाईप लाईन होने पर 07 प्रतिशत जलकर भी देय होगा।

नगरपालिका परिषदों में सम्पत्तिकर को अनिवार्य करों की श्रेणी में वर्गीकरण गृहकर निर्धारण हेतु अधिनियम में संशोधन, करों में वृद्धि एवं एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से नगरपालिका अधिनियम, 1916 धारा 128, 141 (क) एवं 140 यदि में संशोधन किया गया है। जिसकी धारा 141(1) के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर प्रति वर्ग फीट मासिक किराये के दर पर गृहकर निर्धारण अधिनियम में निहित नियमों के अनुसार किया जाना है, परन्तु नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज अपने प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पालिका बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव संख्या 5/3, दिनांक 02 मार्च, 2019 में लिये गये निर्णय के क्रम में जिलाधिकारी सर्किल रेट के आधार पर दर निर्धारण करने का निर्णय लिया गया, तदोपरान्त भवनों एवं सम्पत्तियों पर स्वतः कर (गृहकर/जलकर) निर्धारण नियमावली वर्ष, 2019 एवं कक्षवार दरों की सूची तैयार कराकर प्रकाशन कराये जाने के उपरान्त कोई भी आपत्ति निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने पर नगर पालिका परिषद् गौरा बरहज की बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 3/4, दिनांक 17 जनवरी, 2020 द्वारा स्वतः कर (गृहकर/जलकर) निर्धारण नियमावली वर्ष, 2019 व दरों को लागू करने का अन्तिम निर्णय लिया गया जो राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में मुद्रण हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया, यह नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। तदनुसार कक्षवार (वार्डवार) मासिक किराया प्रति वर्ग फीट की निम्न दरें लागू की जायेंगी—

#### कक्षवार (वार्डवार) निर्धारित प्रस्तावित मासिक किराया (प्रति वर्ग फिट) दरों की सूची

क्र०सं०	कक्ष/वार्ड का नाम	वार्ड संख्या	24 फीट से अधिक चौड़े मार्ग पर दर			24 फीट चौड़े मार्ग पर दर			12 फीट से कम चौड़े मार्ग पर दर			भूमि के सम्बन्ध में	
			आर०सी० सी० छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर०सी० सी० छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर०सी० सी० छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	12 फीट से 24 फीट चौड़े मार्ग पर दर	12 फीट से कम चौड़े मार्ग पर दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जयनगर पश्चिमी	1	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
2	जयनगर बरईया	2	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	पुराना बरहज पूर्वी	3	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
4	आजाद नगर मध्य	4	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
5	तिवारीपुर पश्चिमी	5	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
6	तिवारीपुर पूर्वी	6	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
7	पटेल नगर केवटलिया	7	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
8	आजाद नगर उत्तरी	8	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
9	नन्दना पूर्वी	9	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
10	नन्दना मध्य	10	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
11	गौरा उत्तरी	11	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
12	नन्दना दक्षिणी, पश्चिमी	12	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
13	गौरा मध्य	13	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
14	नन्दना उत्तरी, पश्चिमी	14	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
15	पटेल नगर दक्षिणी, पश्चिमी	15	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
16	गौरा पूर्वी	16	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
17	पटेल नगर उत्तरी, पश्चिमी	17	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
18	पुराना बरहज दक्षिणी, पश्चिमी	18	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
19	आजाद नगर दक्षिणी, पश्चिमी	19	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
20	जयनगर मध्य	20	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
21	पुराना बरहज उत्तरी, पश्चिमी	21	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
22	पटेल नगर मध्य	22	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
23	गौरा पश्चिमी	23	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
24	आजाद नगर दक्षिणी, पूर्वी	24	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
25	पुराना बरहज मध्य	25	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
26	व्यावसायिक दर प्रति वर्ग फीट	—	0.50	0.40	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—

34—नगरपालिका परिषद् गौरा बरहज में नवीन गृहकर वाईलाज लागू होने पर पूर्व की वाईलाज की धारयें व शर्तें मान्य नहीं होंगी।

**नोट**—व्यावसायिक/औद्योगिक, भवन/भूमि होने की दशा में जिलाधिकारी किराया प्रति वर्ग फीट माह दर लागू होगा तथा इस पर कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

ह0 (अस्पष्ट),  
अध्यक्ष,  
नगरपालिका परिषद्, गौरा बरहज,  
जनपद देवरिया।

### सूचना

साझेदारी अनुबन्ध विस्तार-वीर इंजीनियरिंग वर्क्स सिविल लाइन, रोड, राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र में कुल छः पार्टनर कार्यरत क्रमशः रविन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 बी0सी0 शर्मा, राजीव शर्मा पुत्र स्व0 बी0सी0 शर्मा प्रेमशंकर ओझा पुत्र श्री धर्मदेव ओझा, अमिताभ भट्टाचार्या पुत्र श्री एन0एन0 भट्टाचार्या, लल्लन यादव पुत्र श्री रामप्रीत यादव एवं सुरेश यादव पुत्र श्री अभिनन्दन यादव हैं जिनमें से पहले दो को छोड़कर बाकी पार्टनर स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं। फर्म का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये निम्न पांच नये पार्टनर बन रहे हैं। जिनके नाम क्रमशः अंकित शर्मा पुत्र श्री रविन्द्र शर्मा, अंकुर शर्मा पुत्र रविन्द्र शर्मा, रीता शर्मा पत्नी श्री रविन्द्र शर्मा, सुषमा शर्मा पत्नी श्री राजीव शर्मा एवं रितिका शर्मा पत्नी श्री अंकित शर्मा है। अब वीर इंजीनियरिंग वर्क्स कुल साझेदारों की संख्या सात हो गयी है नये अनुबन्ध के बावत् किसी साझेदार को कोई आपत्ति नहीं है। सभी साझेदारों के सहमति से जारी हुआ है। फर्म पंजीकरण स्थिति यथावत् रहेगी।

राजीव शर्मा।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अभय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राधेकृष्ण श्रीवास्तव, निवासी 606/513, पुराना कटरा, जनपद-प्रयागराज के पुत्र अंश श्रीवास्तव (ANSH SRIVASTAVA) का नाम कहीं-कहीं सक्षम श्रीवास्तव (SAKSHAM SRIVASTAVA) लिखा हुआ है। जिसकी जन्म तिथि 19 अक्टूबर, 2003 है। ये दोनों नाम मेरे पुत्र के ही हैं और भविष्य में मेरे पुत्र को अंश श्रीवास्तव (ANSH SRIVASTAVA) के नाम से जाना जायेगा।

अभय कुमार श्रीवास्तव।

### सूचना

एतद्वारा मैं घोषणा करता हूं कि सुरेन्द्र कुमार और सुरेन्द्र कुमार विक्रम पुत्र श्री चौहारजा प्रसाद, निवासी सी-1245 एम0आई0जी0, राजाजीपुरम्, लखनऊ एक ही व्यक्ति हैं। मेरे सेवा से सम्बन्धित पत्रजातों में मेरा नाम सुरेन्द्र कुमार है। मैं घोषणा करता हूं मुझे भविष्य में भी सुरेन्द्र कुमार विक्रम के नाम से जाना जायेगा।

सुरेन्द्र कुमार विक्रम।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स निटको टैक्नोलॉजी, ए-4/14, सेक्टर-80, फेस-2, नोएडा, जिला-

गौतमबुद्धनगर-201305 की साझीदारी में श्री राजकुमार एवं श्री सन्तू लाल साझीदार थे। दिनांक 01 जुलाई, 2020 को सीमा चौहान फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुई है तथा दिनांक 01 जुलाई, 2020 को श्री सन्तू लाल ने अपना हिसाब-किताब ले-देकर फर्म की साझीदारी से अलग हो गये हैं। अब फर्म की साझीदारी में वर्तमान में श्री राजकुमार एवं सीमा चौहान साझीदार है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजकुमार,

साझीदार,

मेसर्स निटको टैक्नोलॉजी,

ए-4/14, सेक्टर-80, फेस-2,

नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर-201305।

### NOTICE

I, Kanchan Singh R/o 1099 Ashiyana Colony, Kanpur Road, Lucknow, U.P. Before marriage my name was Ms. Kanchan Ojha D/o Mr. Satya Narayan Ojha. I got married to Mr. Padam Mohan Singh on April 22, 1990. After marriage my surname was changed in future I will be known as Kanchan Singh.

KANCHAN SINGH,

Deponent.

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आर0एन0 अग्रवाल पता डी-5, बसन्त बिहार कमलानगर, आगरा, ए0जी0 8143 में 01 अप्रैल, 2007 से फर्म में साझीदार 1-रमेश चन्द्र मित्तल, 2-रीता अग्रवाल थे व दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से श्री रसिक अग्रवाल फर्म में साझीदार के रूप में शामिल हुये तथा 01 सितम्बर, 2020 से रमेश चन्द्र मित्तल फर्म से अपनी स्वेच्छा से भागीदारी से अलग हुये हैं। दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से फर्म में 1-रीता अग्रवाल, 2-रसिक अग्रवाल साझीदार हैं तथा किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

रीता अग्रवाल,

साझीदार,

मेसर्स आर0एन0 अग्रवाल,

डी-5 बसन्त बिहार कमलानगर,

आगरा।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "करीम राईस मिल", रामपुर रोड कैमरी, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्री वकील अहमद पुत्र श्री जलील अहमद, निवासी मोहल्ला सिंघाड़ियान, केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर व श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री हबीब अहमद, निवासी मोहल्ला सिंघाड़ियान, केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर व श्रीमती नथिया पुत्री श्री नजीर अहमद पत्नी श्री अब्दुल रशीद, निवासी मोहल्ला सिंघाड़ियान, केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर तथा श्रीमती मुन्नी बेगम पुत्री श्री धूमी पत्नी श्री वकील अहमद, निवासी मोहल्ला सिंघाड़ियान, केमरी

बिलासपुर, जिला रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्री फखरुद्दीन पुत्र श्री अली अहमद, निवासी मोहल्ला इमामबाड़ा, केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर शामिल हो गये हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर्ड पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में छः पार्टनर श्री कबीर अहमद, श्री जलालुद्दीन, श्री रफीक अहमद, श्रीमती रहमत जहां, श्रीमती निलोफर जहां तथा श्री फखरुद्दीन रह गये हैं।

कबीर अहमद,  
पार्टनर,  
फर्म मेसर्स "करीम राईस मिल",  
रामपुर रोड कैमरी,  
जिला रामपुर (यू0पी0)।